सितम्बर 2026

हिन्दी मासिक पत्रिका | ₹15

मुकुंद लेखनी



योगी का 'मिशन यूपी'

युवा व महिलाओं से सीधा संवाद, किया चुनावी जीत का शंखनाद

VPL BLOOD BANK & COMPONENT CENTER

Safe Blood | Healthy Tomorrow

Donate Blood Save Lives

रक्तदान महादान

Every Drop Counts...
Give Blood Give Hope

6th ANNIVERSARY



6 Years of Saving Lives Through Voluntary Blood Donation

VOLUNTARY BLOOD DONATION
A Gift of Life

SAFE & QUALITY BLOOD PRODUCTS
For a Healthier Society

SUPPORTING PATIENTS
In Critical Care

BUILDING A HEALTHIER COMMUNITY
Together We Can

COMPONENT THERAPY
Right Blood | Right Patient Right Time

आप सभी के सहयोग और विश्वास के लिए
हार्दिक धन्यवाद!

Together We Save Lives

VPL BLOOD BANK & COMPONENT CENTER
Belhaiya Chauraha, Siddarthnagar

Mobile:
9452816654

वर्ष : 01, अंक : 02, सितम्बर -2026

UPHIN/26/A6820

इस अंक में 1

मुकुंद लेखनी

–संपादक–

सौरभ भट्ट

मो.– 9918888489

उप सम्पादक

सन्दीप सिंह

मो.– 9450263005

उत्तर प्रदेश ब्यूरो

अशोक मिश्रा

मो.– 6393514145

संपादकीय कार्यालय

आवास नं0 : 33,

साईं रेजिडेंसी, उत्तरधौना,

लखनऊ,

उत्तर प्रदेश – 226028

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सौरभ भट्ट के द्वारा आवास नं0 : 33, साईं रेजिडेंसी, उत्तरधौना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226028 से प्रकाशित तथा लक्ष्मी ऑफसेट 539क/100क/240, देवपुरी भवन, संजय गांधी पुरम, फैजाबाद रोड लखनऊ से मुद्रित।

सौरभ भट्ट

सम्पादक

मो.– 9918888489

हमें अपने पाठकों की प्रतिक्रिया और विचारों को जानना अच्छा लगेगा। यदि पत्रिका की किसी भी सामग्री पर आपको आपत्ति है, तो कृपया हमें अपने सुझाव भेजें।

हम नए लेखों का भी स्वागत करते हैं! यदि आप किसी विषय पर लेख भेजना चाहते हैं, तो कृपया उसे हमें भेजें। हम आपके लेख पर विचार करेंगे।

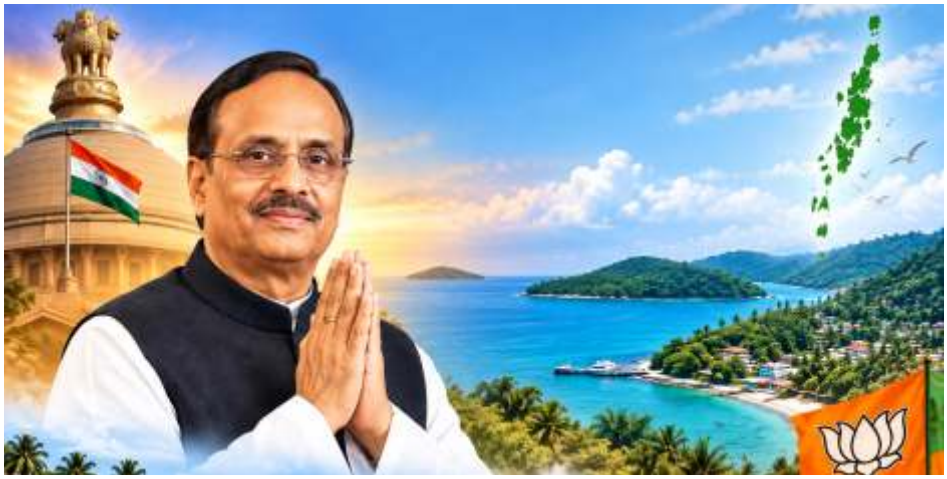
ईमेल पता : mukundlekhni@gmail.com

फोन नंबर : 9918888489

पत्रिका में समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय मान्य होगा।



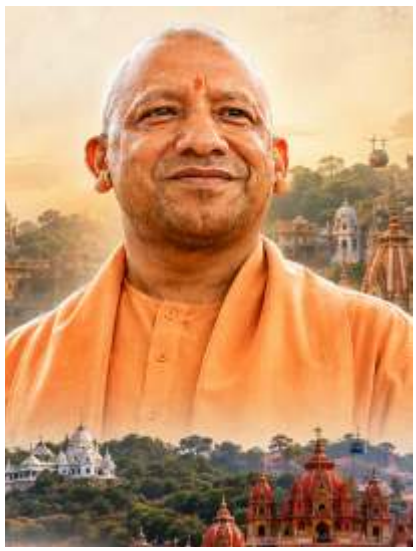
6 इमारतें नहीं भारत के भविष्य की ढहती नींव



13 सम्मानजनक विदाई या 2027 के लिए भाजपा का बड़ा सियासी समीकरण?



16 हिंदी : हमारी आवाज, हमारी स्मृति और ...



28 आस्था से विकास तक: योगी के ...



सौरभ भट्ट
संपादक

अखिलेश का 'नीला दांव'

क्या बदलेगा यूपी का सियासी समीकरण?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिसात बिछने से पहले ही सामाजिक समीकरणों को साधने की कवायद तेज हो जाती है। आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव की राजनीति में दलित वर्ग को लेकर बढ़ता फोकस इसी व्यापक रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसी को राजनीतिक हलकों में 'नीला दांव' कहा जा रहा है।

'नीला' रंग भारतीय राजनीति में लंबे समय से दलित आंदोलन और डॉ. भीमराव आंबेडकर की राजनीतिक विरासत से जुड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने इसी सामाजिक-राजनीतिक पहचान को अपनी राजनीति का केंद्रीय आधार बनाया। ऐसे में समाजवादी पार्टी का दलित मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास राज्य के पारंपरिक जातीय समीकरणों पर असर डाल सकता है।

दलित वोट पर नजर

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में दलित मतदाता लंबे समय से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति रहे हैं। हालांकि यह वर्ग पूरी तरह एकसमान नहीं है। जाटव सहित विभिन्न दलित समुदायों की राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग-अलग चुनावों और क्षेत्रों में अलग रूप लेती रही हैं।

समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सामाजिक राजनीति में यादव और मुस्लिम मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने इस आधार के बाहर भी अपना सामाजिक विस्तार करने की कोशिश की है। दलित समुदाय तक पहुंच बढ़ाना इसी प्रयास की एक कड़ी माना जा सकता है।

आंबेडकर की विरासत का सवाल

अखिलेश यादव की राजनीति में डॉ. आंबेडकर के विचारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों का उल्लेख पहले की तुलना में अधिक दिखाई देता है। इसका राजनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंबेडकर की विरासत केवल प्रतीकात्मक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी से जुड़ा प्रश्न है।

यहां सवाल सिर्फ आंबेडकर की तस्वीर या प्रतीकों तक सीमित नहीं है। दलित मतदाता यह भी देखते हैं कि राजनीतिक दल टिकट वितरण, संगठन में प्रतिनिधित्व, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक मुद्दों पर किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं।

बसपा के लिए चुनौती या अलग राजनीतिक स्पेस?

दलित राजनीति की चर्चा उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ के बिना पूरी नहीं हो सकती। लंबे समय तक बसपा ने दलित मतदाताओं के बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़े रखा। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी दलित वर्ग में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश करती है, तो इसका सीधा संबंध प्रदेश के विपक्षी राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ता है।

हालांकि यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि दलित मतदाता किसी एक दल की ओर सामूहिक रूप से स्थानांतरित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना काफी विविध है और क्षेत्र, जाति, स्थानीय नेतृत्व तथा उम्मीदवार जैसे कारक चुनावी व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।

गठबंधन की राजनीति भी अहम

अखिलेश यादव की रणनीति को केवल एक समुदाय को जोड़ने की कोशिश के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति अक्सर सामाजिक समूहों के बीच व्यापक गठबंधन बनाने पर निर्भर करती है।

यदि समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अन्य सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक तालमेल बनाने में सफल होती है, तो उसके सामने एक व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करने का अवसर हो सकता है। लेकिन इस तरह के गठबंधन को जमीन पर संगठन, स्थानीय नेतृत्व और सीटों के बंटवारे जैसे सवालों से भी गुजरना होगा।

प्रतीक से आगे कितना असर?

'नीला दांव' की असली परीक्षा चुनावी भाषणों या प्रतीकों से आगे होगी। दलित मतदाताओं के बीच किसी राजनीतिक दल की स्वीकार्यता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वह प्रतिनिधित्व, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों पर क्या रुख और कार्यक्रम पेश करता है।

इसके अलावा उम्मीदवार चयन और संगठन में दलित नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। यदि राजनीतिक संदेश और संगठनात्मक संरचना में समानता दिखाई देती है, तो उसका प्रभाव अलग हो सकता है; यदि दोनों में अंतर रहता है, तो राजनीतिक संदेश की प्रभावशीलता सीमित भी हो सकती है।

चुनावी गणित से ज्यादा सामाजिक संदेश

अखिलेश यादव का 'नीला दांव' केवल वोटों के गणित के रूप में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती सामाजिक राजनीति के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है। दलित राजनीति में नए समीकरण बनाने की कोशिशें बताती हैं कि आने वाले चुनावों में सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और आंबेडकरवादी राजनीति की भाषा फिर प्रमुख भूमिका निभा सकती है।

आखिरकार, किसी भी चुनाव में रणनीति की सफलता का फैसला मतदाता करते हैं। 'नीला दांव' कितना प्रभावी साबित होगा, इसका उत्तर चुनावी मैदान में उम्मीदवारों, गठबंधनों, स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं के वास्तविक मतदान व्यवहार से ही सामने आएगा।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मतदाताओं को लेकर सक्रियता बढ़ रही है और अखिलेश यादव की रणनीति ने चुनावी विमर्श में एक नया सामाजिक कोण जरूर जोड़ दिया है।



डिजिटल भारत में रोजगार और स्वरोजगार की नई संभावनाएं



परमजीत सिंह चंधोक

भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल भुगतान के विस्तार ने ई-कॉमर्स को देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। आज ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और गांवों तक भी पहुंच चुकी है। ऐसे में ई-कॉमर्स क्षेत्र रोजगार और स्वरोजगार के लिए एक भरोसेमंद और प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है।

ई-कॉमर्स के माध्यम से युवाओं के लिए अनेक रोजगार अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ऑनलाइन सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी, ग्राहक सेवा, सोशल मीडिया प्रबंधन, वेबसाइट संचालन और कंटेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

ई-कॉमर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह छोटे व्यापारियों और सामान्य लोगों को भी अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर देता है। कोई व्यक्ति घर से बने उत्पाद, कपड़े, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री या स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के ग्राहकों तक पहुंचा सकता है।

महिलाओं और युवाओं के लिए भी यह क्षेत्र आत्मनिर्भर बनने का एक मजबूत माध्यम साबित हो रहा है। सीमित संसाधनों के साथ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग कर अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है।

ई-कॉमर्स में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ भरोसेमंद कार्य वातावरण की आवश्यकता भी बढ़ी है। फर्जी ऑनलाइन नौकरियों और ठगी के मामलों के बीच युवाओं को सुरक्षित और विश्वसनीय रोजगार उपलब्ध कराना जरूरी है।

कंपनियों और ऑनलाइन व्यवसायों को अपने कर्मचारियों तथा सहयोगियों के लिए स्पष्ट नियम, उचित मेहनताना, समय पर भुगतान और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। रोजगार तभी स्थायी और प्रभावी बन सकता है, जब उसमें विश्वास और पारदर्शिता हो।

ई-कॉमर्स के क्षेत्र में सफलता के लिए डिजिटल कौशल बेहद जरूरी है। युवाओं को ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान, ग्राहक सेवा और तकनीकी ज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित होना चाहिए।

सरकार और निजी संस्थानों को भी युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकें।

ई-कॉमर्स भारत में रोजगार की नई क्रांति का माध्यम बन सकता है। यह केवल नौकरी पाने का नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार तैयार करने का भी अवसर प्रदान करता है।

जरूरत है कि इस क्षेत्र में ईमानदारी, पारदर्शिता और भरोसे को प्राथमिकता दी जाए। यदि ई-कॉमर्स के माध्यम से सुरक्षित और स्थायी रोजगार के अवसर विकसित किए जाएं, तो यह देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ई-कॉमर्स का सही उपयोग केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों के लिए भरोसेमंद रोजगार और बेहतर भविष्य का रास्ता भी बन सकता है।

इमारतें नहीं भारत के भविष्य की ढहती नींव





अमल मिश्र

दिल्ली के सत्य निकेतन में एक छात्रावास (पीजी) की पाँच मंजिला इमारत का अचानक ढह जाना केवल एक भवन-दुर्घटना नहीं है। यह उन लाखों परिवारों के सपनों पर गिरा हुआ मलबा है, जो अपने बच्चों को छोटे शहरों और कस्बों से दिल्ली जैसे महानगरों में इस विश्वास के साथ भेजते हैं कि वे वहाँ शिक्षा पाएँगे, प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे, कोई कौशल सीखेंगे और एक दिन अपने परिवार की आर्थिक-सामाजिक स्थिति बदल देंगे। सत्य निकेतन की घटना में मृतकों की संख्या को लेकर बचाव अभियान के दौरान अलग-अलग रिपोर्टें सामने आईं; नवीनतम रिपोर्टों में सात मौतों की पुष्टि की गई है। जिस भवन में विद्यार्थी रह रहे थे, वह पुराना था और उसके पुनर्निर्माण तथा तहखाने में चल रहे कार्य को लेकर भी प्रश्न उठे हैं। मलबे के नीचे दबा प्रत्येक शरीर अपने पीछे केवल एक परिवार का शोक नहीं छोड़ता। उसके साथ एक माँ की वर्षों की बचत, पिता की अनगिनत अतिरिक्त मेहनत, बहन-भाई की आशाएँ,

किसी गाँव या छोटे शहर की आकांक्षा और स्वयं उस युवक का वह भविष्य भी दब जाता है जिसे उसने अभी जीना शुरू ही किया था। इन बच्चों और युवाओं के लिए महानगर केवल शहर नहीं होते; वे अवसर का दूसरा नाम होते हैं। वे घर से निकलते समय अपने साथ एक छोटा-सा बस्ता, कुछ कपड़े, पुस्तकों का ढेर और आँखों में बहुत बड़ा भविष्य लेकर निकलते हैं। पीछे रह जाते हैं माता-पिता, जो अपनी आवश्यकताओं को काटकर हर महीने कुछ हजार रुपये भेजते हैं। कभी खेत की उपज बेचकर, कभी छोटी नौकरी की आय से, कभी उधार लेकर, कभी वर्षों की बचत तोड़कर। उन्हें विश्वास होता है कि उनका बच्चा पढ़-लिखकर उनके संघर्ष का अर्थ बदल देगा। इसलिए जब ऐसा बच्चा किसी असुरक्षित भवन में जलकर मरता है, पानी में डूब जाता है अथवा किसी जर्जर इमारत के नीचे दब जाता है, तो प्रश्न केवल यह नहीं होता कि मृत्यु का तत्काल कारण क्या था। प्रश्न यह होता है कि उस मृत्यु को होने से रोकने के लिए जिन व्यवस्थाओं का निर्माण समाज ने किया था, वे कहाँ थीं?

अभी कुछ ही महीने पहले लखनऊ के अलीगंज में एक वाणिज्यिक भवन में लगी भीषण आग ने इसी प्रश्न को और अधिक निर्मम ढंग से सामने रखा था। 22 जून 2026 की उस घटना में कम-से-कम 15 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें अधिकांश युवा विद्यार्थी अथवा प्रशिक्षण और कार्य से जुड़े युवक-युवतियाँ थे। प्रारंभिक रिपोर्टों में भवन के उपयोग, अग्निसुरक्षा और स्वीकृत निर्माण से जुड़े गंभीर प्रश्न सामने आए। कई लोग धुएँ से दम घुटने के कारण मारे गए और कुछ ने जान बचाने के लिए ऊँचाई से छलाँग लगाने की कोशिश की। उस घटना का सबसे हृदयविदारक पक्ष यह था कि आग से घिरे युवाओं ने अपने परिवारों को फोन किया। कुछ अंतिम फोन कॉलों में सहायता के लिए पुकार थी। कल्पना कीजिए उस माता-पिता की मानसिक अवस्था की, जिसके मोबाइल पर उसका बेटा या बेटी अंतिम बार यह कह रहा हो कि वह संकट में है और उसे बचाया जाए। आधुनिक भारत के तकनीकी और आर्थिक विकास की समूची चमक उस क्षण कितनी असहाय दिखाई देती होगी! और यह कोई अकेली घटना नहीं है। जुलाई 2024 में दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में वर्षा का पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उस समय की सामग्री में भी इस घटना का उल्लेख है कि नाले के फटने के बाद बेसमेंट में पानी भर गया और तीन अभ्यर्थी उसमें फँस गए। उस दुर्घटना में भी मरने वाले कोई सामान्य अर्थ में 'भीड़' नहीं थे। वे अपने-अपने परिवारों के लिए भविष्य की सबसे बड़ी आशा थे। इन तीनों घटनाओं के बीच एक गहरी समानता है। स्थान अलग हैं, दुर्घटना के स्वरूप अलग हैं, परिस्थितियाँ अलग हैं, परन्तु इनके केंद्र में एक ही चीज दिखाई देती है—अवसर की तलाश में घर से निकला युवा और उसके चारों ओर बनी अपर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था।



भारत का महानगरीय विस्तार जिस गति से हुआ है, उस गति से उसके नागरिक-सुरक्षा तंत्र का विस्तार नहीं हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी यह रेखांकित करता है कि भारत तीव्र शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है और जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास तथा आधारभूत सेवाओं पर बढ़ता दबाव बच्चों और युवाओं के लिए नए जोखिम पैदा कर रहा है। अनुमान है कि 2036 तक भारत के शहरों में लगभग 60 करोड़ लोग रह सकते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ हमें 'विकास' की अपनी परिभाषा पर पुनर्विचार करना होगा। क्या ऊँची इमारतें विकास हैं? क्या चमकती सड़कों, विशाल मेट्रो प्रणालियों, स्मार्ट शहरों और डिजिटल सेवाओं का विस्तार ही विकास का पर्याप्त प्रमाण है? यदि उन्हीं शहरों में पढ़ने आया एक विद्यार्थी ऐसे भवन में रहने के लिए विवश है जिसकी संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, जिस छात्रावास का नियमित निरीक्षण नहीं होता, जिस कोचिंग भवन में आपातकालीन निकास पर्याप्त नहीं है अथवा जहाँ अग्निशमन व्यवस्था केवल कागज पर मौजूद है, तो विकास की वह चमक भीतर से खोखली है।

यहाँ दोष किसी एक सरकार या किसी एक राजनीतिक दल के खाते में डाल देना समस्या को बहुत छोटा कर देना होगा। सरकारें बदलती हैं, अधिकारी बदलते हैं, नगर निकायों के स्वरूप बदलते हैं, नीतियाँ बदलती हैं; परन्तु प्रशासनिक संस्कृति, निरीक्षण की कमजोरी, नियमों के अनुपालन की अनदेखी, अवैध निर्माण के प्रति सामाजिक सहनशीलता और व्यावसायिक लाभ को मानवीय सुरक्षा से ऊपर रखने की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसलिए उत्तरदायित्व भी बहुस्तरीय होना चाहिए। निर्माता उत्तरदायी है, भवन-मालिक उत्तरदायी है, संस्थान संचालक उत्तरदायी है, नगर नियोजन व्यवस्था उत्तरदायी है, अग्निशमन तंत्र उत्तरदायी है और निरीक्षण करने वाली संस्थाएँ भी उत्तरदायी हैं। समाज भी तब उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता जब वह किसी अवैध अतिरिक्त मंजिल को यह कहकर स्वीकार कर ले कि 'सब जगह ऐसा ही होता है'। माता-पिता अपने बच्चों को भेजते समय भवन की सुरक्षा की जाँच करने की स्थिति में नहीं होते; इसलिए उनके विश्वास का संरक्षण राज्य और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। विश्व के कुछ देशों ने भवन-सुरक्षा को केवल निर्माण अनुमति का विषय न मानकर पूरे भवन-जीवन चक्र का विषय बनाया है। ब्रिटेन में भवन सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ऊँची जोखिम वाली इमारतों के लिए डिजाइन, निर्माण और उपयोग की अवस्थाओं में अलग-अलग उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं और भवन सुरक्षा नियामक की संस्थागत भूमिका बनाई गई है। निर्धारित श्रेणी की इमारतों के लिए पंजीकरण और सुरक्षा संबंधी कानूनी दायित्व भी हैं। विश्वविद्यालयों और छात्रावासों जैसे आवासीय भवनों को भी जोखिम की दृष्टि से देखा जाता है। सिंगापुर का उदाहरण भी उपयोगी है। वहाँ छात्रावासों के लिए नियोजन संबंधी स्पष्ट नियम हैं और अग्निसुरक्षा प्रमाणन जैसी आवश्यकताओं के साथ निरीक्षण की व्यवस्था जुड़ी हुई है। वहाँ बहुमंजिला छात्रावासों के लिए स्वचालित और मैनुअल दोनों प्रकार की अग्नि-सूचना प्रणालियों की आवश्यकताएँ निर्धारित हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे देशों में दुर्घटनाएँ नहीं होतीं; कोई भी व्यवस्था पूर्णतः दुर्घटनामुक्त नहीं हो सकती। अंतर यह है कि वहाँ जोखिम को पहले से पहचानना और उसे संस्थागत रूप से कम करना शासन का नियमित कार्य माना जाता है। भारत के लिए भी इसी प्रकार की दृष्टि आवश्यक है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्रावास, पेइंग गेस्ट आवास,



प्रतियोगी परीक्षा के कोचिंग केंद्र, निजी प्रशिक्षण संस्थान और महानगरों में विद्यार्थियों के लिए बने किराये के आवास—इन सबको एक साझा 'युवा सुरक्षा तंत्र' के अंतर्गत देखने की आवश्यकता है। केवल दुर्घटना के बाद सीलिंग, जाँच समिति और मुआवजा पर्याप्त नहीं हो सकते।

प्रत्येक छात्रावास और छात्र-आवास (पेइंग गेस्ट) का डिजिटल सुरक्षा-पंजीकरण हो। भवन की संरचनात्मक स्थिति, स्वीकृत नक्शा, वास्तविक मंजिलों की संख्या, विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन प्रमाणपत्र, आपातकालीन निकास, जल निकासी, अधिकतम आवास क्षमता और अंतिम सुरक्षा निरीक्षण की तिथि सार्वजनिक की जाए। जिस भवन में सैकड़ों विद्यार्थी रहते हैं, उसकी सुरक्षा संबंधी जानकारी केवल किसी कार्यालय की फाइल में बंद क्यों रहे? जिस प्रकार अस्पताल की विश्वसनीयता, विद्यालय की मान्यता या किसी विश्वविद्यालय की मान्यता सार्वजनिक रूप से देखी जा सकती है, उसी प्रकार छात्रावास की सुरक्षा स्थिति भी विद्यार्थी और अभिभावक देख सकें। इसके साथ ही 'दुर्घटना के बाद मुआवजा' की मानसिकता से 'दुर्घटना से पहले रोकथाम' की व्यवस्था की ओर बढ़ना होगा। मुआवजा मृत व्यक्ति को वापस नहीं लाता। वह केवल जीवित परिवार के आर्थिक संकट को कुछ समय के लिए कम कर सकता है। जिस बच्चे के लिए माता-पिता ने जीवन भर अपनी इच्छाएँ स्थगित कीं, उसके स्थान पर कोई राशि नहीं रखी जा सकती।

विद्यालय और महाविद्यालयों की सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ भी व्यापक आपदा-जोखिम न्यूनीकरण, समुदाय आधारित तैयारी और बच्चों को जोखिम पहचानने तथा आपातस्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करने पर बल देता है। भारत में भी यह प्रशिक्षण केवल औपचारिक मॉक ड्रिल तक सीमित न रहकर वास्तविक आपदा-तैयारी का हिस्सा बनना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम इन युवाओं को देखते किस दृष्टि से हैं। क्या वे केवल कोचिंग के ग्राहक हैं? किसी मकान मालिक के किरायेदार हैं? किसी निजी संस्थान के शुल्कदाता हैं? किसी शहर की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले उपभोक्ता हैं? या वे राष्ट्र की जीवित पूँजी हैं? वास्तव में वे भारत की सबसे बड़ी पूँजी हैं। जिस युवा ने अपने गाँव से दिल्ली की ट्रेन पकड़ी है, उसके भीतर केवल एक व्यक्तिगत सपना नहीं होता। वह अपने परिवार को ऊपर उठाने की इच्छा लेकर आता है। वह डॉक्टर बन सकता है, अभियंता बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, कलाकार, वास्तुविद, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक, प्रशासक, उद्यमी या शोधकर्ता बन सकता है। कोई एक दिन किसी प्रयोगशाला में भारत की अगली तकनीकी उपलब्धि का हिस्सा बन सकता है। कोई किसी विश्वविद्यालय में ज्ञान की नई सीमा खोज सकता है। कोई गाँव लौटकर अपने क्षेत्र की शिक्षा बदल सकता है। किसी के भीतर भविष्य का शिक्षक है, किसी में वैज्ञानिक, किसी में कलाकार, किसी में प्रशासक और किसी में ऐसा नागरिक जो समाज की दिशा बदल सकता है। हमारे लिए इन बच्चों की मृत्यु इसलिए भी राष्ट्रीय क्षति है कि भारत आज जनसांख्यिकीय दृष्टि से युवा राष्ट्र है। इस युवा शक्ति को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदलने के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वास्थ्य के साथ सुरक्षा भी अनिवार्य है। सुरक्षित आवास और सुरक्षित शिक्षण-परिसर कोई विलासिता नहीं, शिक्षा के अधिकार की आधारभूत शर्त हैं।

इसलिए अब हर ऐसी घटना के बाद केवल संवेदना व्यक्त करने और कुछ लाख रुपये की सहायता घोषित करने से आगे बढ़ना होगा। संवेदना आवश्यक है, सहायता भी आवश्यक है, पर उसके बाद उस व्यवस्था को बदलना अधिक आवश्यक है जिसने दुर्घटना की संभावना पैदा की थी। सत्य निकेतन के मलबे में दबे विद्यार्थी, अलीगंज की आग में बुझी युवा आँखें और राजेंद्र नगर के जलमग्न बेसमेंट में समाप्त हुए तीन सपने हमें एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं—भारत अपने भविष्य की रक्षा कब करेगा? यह प्रश्न किसी दल से नहीं, पूरे राष्ट्र से है। माता-पिता अपने बच्चों को महानगरों में इसलिए नहीं भेजते कि वे असुरक्षित इमारतों में अपनी जान गँवाएँ। वे उन्हें इसलिए भेजते हैं कि वे लौटकर घर की परिस्थितियाँ बदलें। किसी किसान का बेटा अधिकारी बने, किसी छोटे दुकानदार की बेटी वैज्ञानिक बने, किसी शिक्षक का पुत्र शोधकर्ता बने, किसी निम्न-मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा उद्यम खड़ा करे—भारत की वास्तविक प्रगति की कहानी इन्हीं यात्राओं से लिखी जानी है। इसलिए किसी विद्यार्थी की मृत्यु को केवल 'दुर्घटना' कहकर आगे बढ़ जाना उस शब्द के पीछे छिपे सामाजिक अपराध को छोटा करना है। दुर्घटना वह होती है जिसे रोकना संभव न हो; परन्तु जर्जर भवन, अवैध निर्माण, बंद निकास, अपर्याप्त अग्निसुरक्षा, जल निकासी की विफलता और नियमों की अनदेखी यदि पहले से ज्ञात जोखिम हैं, तो उनके बाद होने वाली मृत्यु को केवल नियति नहीं कहा जा सकता। भारत को अपने बच्चों के लिए ऐसे शहर बनाने होंगे जहाँ सपने लेकर आने वाला विद्यार्थी अपने माता-पिता को यह कह सके—"मैं यहाँ सुरक्षित हूँ।" क्योंकि राष्ट्र की सबसे ऊँची इमारत संसद या सचिवालय नहीं होती; राष्ट्र की सबसे ऊँची इमारत उसके बच्चों के सपनों से बनती है। और यदि उन सपनों को सुरक्षित रखने की क्षमता हमारे पास नहीं है, तो हमें अपने विकास की पूरी अवधारणा पर फिर से विचार करना होगा। सत्य निकेतन का मलबा हट जाएगा। अलीगंज की राख ठंडी हो जाएगी। राजेंद्र नगर की वह बरसात भी इतिहास का एक पन्ना बन जाएगी। कुछ दिनों बाद समाचार-पत्रों की सुर्खियाँ बदल जाएँगी। किंतु जिन घरों में उस दिन से किसी कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है, वहाँ समय कभी सामान्य नहीं होगा।

भारत को यह तय करना है कि वह इन बंद दरवाजों की संख्या बढ़ने देगा या ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें किसी माँ को अपने बेटे की अंतिम फोन कॉल का इंतजार न करना पड़े, किसी पिता को मलबे में अपने बच्चे का चेहरा न तलाशना पड़े और कोई युवा अपने सपनों के शहर में पहुँचकर उस शहर की लापरवाही का शिकार न बने। आखिर ये बच्चे केवल किसी परिवार के चिराग नहीं हैं। ये उस भारत की रोशनी हैं, जिसे हम विकसित, समृद्ध, ज्ञानवान और मानवीय राष्ट्र बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। उस भविष्य की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी भर नहीं, पूरे समाज का नैतिक दायित्व है।

लेखक स्वतंत्र स्तंभकार है।



मनुष्य वस्तुओं से नहीं, स्मृतियों से बनता है



डॉ लीना मिश्र

मनुष्य के संबंधों की दुनिया बड़ी विचित्र है। यहाँ प्रेम का मूल्य हमेशा उस मात्रा से निर्धारित नहीं होता, जितना किसी ने हमारे लिए किया है; कई बार उसका मूल्य इस बात से निर्धारित होने लगता है कि हमें उसके होने का अनुभव कितनी बार और किस रूप में हुआ। जो व्यक्ति हमारे जीवन की अधिकांश आवश्यकताओं को चुपचाप पूरा करता रहता है, जिसकी उपस्थिति इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि हम उसे अपने जीवन का अनिवार्य अंग मान लेते हैं, उसके योगदान का बोध धीरे-धीरे हमारी चेतना में सामान्य होकर रह जाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति हमारे जीवन में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होता, किंतु जन्मदिन, पर्व, उपलब्धि या किसी विशेष अवसर पर एक छोटा-सा उपहार लेकर सामने आ जाता है, उसकी वह छोटी-सी अभिव्यक्ति भी हमारे भीतर असाधारण अर्थ ग्रहण कर लेती है। यह मनुष्य के मन की एक गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विडंबना है।

वास्तव में उपहार वस्तु का नाम नहीं है; वह स्मरण का दृश्य रूप है। किसी ने हमें क्या दिया, इसका महत्व प्रायः उतना नहीं होता जितना इस बात का कि उसने हमें याद किया। उपहार हाथ में आने वाली वस्तु है, किंतु उसका वास्तविक मूल्य उस भाव में निहित होता है जो उसके पीछे छिपा होता है। एक साधारण-सी कलम यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर देता है कि "यह वस्तु उसे पसंद आएगी", तो वह महँगी वस्तु से अधिक आत्मीय हो सकती है। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति यदि हमारे जीवन के लिए अपना समय, श्रम, सुविधा, नींद, धन और जीवन का एक बड़ा हिस्सा लगा देता है, तो उसके द्वारा किए गए इन असंख्य त्यागों को हम कई बार उपहार की श्रेणी में रख ही नहीं पाते। क्योंकि वे हमारे लिए निरंतर उपलब्ध हैं, इसलिए वे धीरे-धीरे हमारी दृष्टि में कर्तव्य बन जाते हैं।

यहीं से संबंधों की सबसे सूक्ष्म त्रासदी जन्म लेती है—जो व्यक्ति सबसे अधिक देता है, वह सबसे कम दिखाई देता है। माँ अपने बच्चे के लिए वर्षों तक जागती है। उसके भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भविष्य और सुख की चिंता करती है। वह शायद ही कभी बच्चे के सामने यह कहती है कि "मैंने तुम्हारे लिए इतना किया।" इसलिए उसका प्रेम बच्चे के जीवन में हवा और प्रकाश की तरह उपस्थित रहता है। बच्चा उसके मूल्य को समझता तो है, किंतु उसका अनुभव उतनी तीव्रता से नहीं करता। वहीं कोई दूर का संबंधी वर्ष में एक बार मिठाई का डिब्बा लेकर आता है और बच्चे को कुछ रुपये या कोई उपहार देता है। बच्चा प्रसन्न होकर उसे याद रखता है। उसके मन में उस व्यक्ति की छवि बन जाती है—"वह मुझे उपहार देता है।" माँ ने जो जीवन दिया, वह अदृश्य रह गया; अतिथि ने जो वस्तु दी, वह स्मृति बन गई।

यह विरोधाभास केवल परिवारों तक सीमित नहीं है। मित्रता, दाम्पत्य, गुरु-शिष्य संबंध, कार्यस्थल और सामाजिक जीवन—हर जगह इसका सूक्ष्म रूप दिखाई देता है। जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी उपलब्धता को हम सुविधा समझने लगते हैं। जो व्यक्ति कभी-कभार उपलब्ध होता है, उसकी थोड़ी-सी उपस्थिति भी विशेष लगती है। मनुष्य का मानस निरंतर प्राप्त होने वाली वस्तु की तुलना में दुर्लभ वस्तु को अधिक मूल्यवान मानने की प्रवृत्ति रखता है। मनोविज्ञान में इसे दुर्लभता की प्रवृत्ति कहा जाता है। जो सहज उपलब्ध है, उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता धीरे-धीरे कम हो सकती है; जो सीमित है, उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह मनुष्य की कृतज्ञता-बोध की सीमा को भी उजागर करता है। अरस्तू ने मनुष्य के सद्गुणों में न्याय, मित्रता और पारस्परिकता को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना था। उनके विचार में मनुष्य अकेला अस्तित्व नहीं है; वह संबंधों के ताने-बाने में जीता है। किंतु संबंधों में पारस्परिकता का अनुभव तभी संभव है जब हम दूसरे के योगदान को देख सकें। समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी का योगदान इतना निरंतर और स्वाभाविक हो जाता है कि हम उसे योगदान मानना ही बंद कर देते हैं।

उदाहरण के लिए, किसी परिवार में एक व्यक्ति वर्षों तक घर की आर्थिक जिम्मेदारी उठाता है। वह बच्चों की फीस भरता है, दवाइयाँ लाता है, घर का किराया देता है, आकस्मिक संकटों में खड़ा होता है और अपनी अनेक इच्छाओं को स्थगित करता रहता है। दूसरी ओर कोई रिश्तेदार त्योहार पर महँगा उपहार लेकर आता है। परिवार के सदस्य उस उपहार की चर्चा करते हैं, उसे संभालकर रखते हैं और देने वाले के प्रति विशेष आत्मीयता अनुभव करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे उस जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति के प्रति कृतघ्न हों। समस्या यह है कि निरंतर त्याग धीरे-धीरे अदृश्य हो गया है। जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं, उसके महत्व को देखने के लिए हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की सजगता चाहिए। ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रेंड रसेल ने मानव संबंधों में सुख और

संतोष के लिए प्रेम, आत्मीयता और दूसरे के प्रति रुचि को महत्त्वपूर्ण माना। उनकी दृष्टि में मनुष्य का सुख केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बनता; वह इस अनुभव से भी बनता है कि हम किसी के जीवन में अर्थ रखते हैं और कोई हमारे जीवन में अर्थ रखता है। यही कारण है कि उपहार की वास्तविक शक्ति उसके मूल्य में नहीं, उसके द्वारा उत्पन्न किए गए "मैं तुम्हें याद करता हूँ" के भाव में होती है। इस संदर्भ में अस्तित्ववादी ऑस्ट्रियाई-इज़रायली दार्शनिक मार्टिन बूबर का "मैं और तुम" का संबंध अत्यंत अर्थपूर्ण हो जाता है। बूबर के अनुसार सच्चा संबंध तब बनता है जब हम दूसरे व्यक्ति को किसी उपयोग या भूमिका के रूप में नहीं, एक पूर्ण अस्तित्व के रूप में देखते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो अनजाने में हम उसे उसकी भूमिका में सीमित कर देते हैं—वह पिता है, माँ है, जीवनसाथी है, भाई है, बहन है, मित्र है, कमाने वाला है, देखभाल करने वाला है। उसकी मनुष्यता उसके दायित्व के पीछे छिप जाती है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति अवसर विशेष पर हमें उपहार देता है, तो वह क्षणभर के लिए हमारी दृष्टि में केवल "व्यक्ति" बनकर उपस्थित होता है और हमें यह अनुभव करा देता है कि उसने हमें हमारी भूमिका से परे याद किया है।

यही कारण है कि कभी-कभी पाँच सौ रुपये का उपहार पाँच लाख रुपये के योगदान से अधिक स्मरणीय हो जाता है।

यहाँ प्रश्न यह नहीं कि कौन अधिक प्रेम करता है। प्रश्न यह है कि प्रेम दिखाई किसका देता है।

मनुष्य केवल प्रेम पाना नहीं चाहता, वह प्रेम का अनुभव भी करना चाहता है। इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। कोई व्यक्ति हमारे लिए जीवन भर संघर्ष कर सकता है, किंतु यदि वह कभी हमारे साथ बैठकर यह न कहे कि "मैं तुम्हारे होने से प्रसन्न हूँ", तो उसके प्रेम का अनुभव कहीं-कहीं अधूरा रह सकता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति वर्ष में दो बार फोन करके केवल इतना कह देता है—"तुम याद आए, इसलिए फोन किया"—और हम उस संबंध को विशेष मान लेते हैं। शब्द छोटा है, किंतु वह हमारी उपस्थिति की पुष्टि करता है।

उपहार इसी पुष्टि का भौतिक रूप है।

लेकिन इस सत्य का एक दूसरा पक्ष भी है। हमें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि जो व्यक्ति उपहार देता है वही अधिक प्रेम करता है और जो जिम्मेदारियाँ निभाता है वह कम प्रेम करता है। कई बार परिस्थितियाँ मनुष्य को अभिव्यक्ति का अवसर ही नहीं देतीं। कोई व्यक्ति परिवार के लिए इतना संघर्ष कर रहा होता है कि उसे उत्सव मनाने, उपहार खरीदने या भावनाओं को शब्द देने का समय नहीं मिलता। उसका प्रेम खर्च किए गए धन में नहीं, उसके त्यागे हुए जीवन में लिखा होता है। समस्या उपहार न देने में नहीं है; समस्या तब है जब जिम्मेदारियाँ निभाने वाला व्यक्ति स्वयं यह अनुभव करने लगे कि उसकी भूमिका को केवल कर्तव्य समझ लिया गया है और उसकी भावनात्मक उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं।

इसीलिए संबंधों में केवल जिम्मेदारियाँ पर्याप्त नहीं होतीं; अभिव्यक्ति भी आवश्यक होती है।

भारतीय चिंतन में "ऋण" की अवधारणा इस प्रश्न को और गहराई देती है। माता-पिता, गुरु, समाज, प्रकृति और पूर्वजों के प्रति मनुष्य के अनेक ऋण माने गए हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने जीवन को स्वतंत्र और स्वनिर्मित उपलब्धि मानकर नहीं चल सकता। उसके अस्तित्व में असंख्य अदृश्य हाथों का योगदान होता है। किंतु आधुनिक जीवन में हम इन ऋणों को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि सुविधा ने कृतज्ञता को और गति ने स्मृति को कमजोर कर दिया है। हम प्राप्त वस्तु देखते हैं, उसके पीछे लगा हुआ जीवन नहीं। किसी किसान के खेत से निकला अन्न हमारे भोजन की थाली में आता है, पर किसान दिखाई नहीं देता। किसी श्रमिक के श्रम से बना घर हमें आश्रय देता है, पर उसका श्रम अदृश्य रहता है। माता-पिता जीवन की आधारभूमि तैयार करते हैं, पर उनकी दिन-रात की चिंता हमारी स्मृति में किसी एक अवसर की घटना की तरह दर्ज नहीं होती। मनुष्य अक्सर परिणाम को देखता है, प्रक्रिया को नहीं; उपहार को देखता है, त्याग को नहीं।

शायद इसी कारण हमारे समय की सबसे बड़ी आवश्यकता महँगे उपहार नहीं, कृतज्ञ दृष्टि है।

हमें उन लोगों को पहचानना सीखना होगा जो हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। जो बिना बताए हमारी कठिनाइयाँ बाँटते हैं, जो संकट में सबसे पहले पहुँचते हैं, जो हमारी असफलताओं में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखते हैं—उनके योगदान को केवल "यह तो उनका कर्तव्य है" कहकर समाप्त कर देना संबंधों की गरिमा को छोटा करना है।

क्योंकि कर्तव्य भी प्रेम का एक रूप हो सकता है। और प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति कभी-कभी उपहार खरीदने में नहीं, किसी के त्याग को पहचान लेने में होती है।

फिर भी, जो व्यक्ति हमारे लिए सब कुछ करता है, उसके लिए कभी-कभी एक छोटा-सा फूल, एक पुस्तक, एक पत्र, एक आलिंगन, एक धन्यवाद या बिना किसी अवसर के दिया गया कोई साधारण उपहार अत्यंत आवश्यक हो सकता है। इसलिए नहीं कि उसे वस्तु चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसे यह अनुभव होना चाहिए कि उसका प्रेम भी देखा गया है। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए वर्षों तक जीवन लगाया है, उसे कभी-कभी यह सुनना चाहिए कि "मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए कितना किया है।" यह वाक्य किसी भी महँगे उपहार से अधिक मूल्यवान हो सकता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के चिंतन में संबंधों की सुंदरता स्वतंत्र आत्मीयता और मानवीय स्पर्श में निहित दिखाई देती है। प्रेम जब केवल दायित्व रह जाता है तो उसमें औपचारिकता का प्रवेश हो सकता है; जब उसमें स्वेच्छा और आत्मीयता जुड़ती है, तभी वह जीवंत रहता है। इसलिए किसी संबंध को जीवित रखने के लिए केवल उसके लिए काम करना पर्याप्त नहीं; उसके भीतर उपस्थित व्यक्ति को भी समय-समय पर देखना आवश्यक है।

यहाँ एक छोटी-सी पारिवारिक घटना बहुत कुछ समझा सकती है। एक पिता अपने बेटे की पूरी शिक्षा का खर्च उठाता है। नौकरी लगने तक उसकी सहायता करता है। बेटे के विवाह, घर और भविष्य के लिए अपनी बचत तक लगा देता है। बेटा अपने पिता से प्रेम करता है, किंतु इन सबको जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया मानता रहता है। एक दिन उसका कोई मित्र उसके जन्मदिन पर एक साधारण-सी पुस्तक देता है, जिसके पहले पृष्ठ पर लिखता है—"तुम्हारी मित्रता मेरे जीवन की सुंदर स्मृतियों में से एक है।" वर्षों बाद भी वह पुस्तक उसके पास सुरक्षित रहती है। पिता ने जीवन दिया था, मित्र ने उस जीवन की एक अनुभूति को शब्द दिया। दोनों प्रेम करते थे, पर दोनों के प्रेम की मनोवैज्ञानिक अनुभूति अलग थी। इसलिए संबंधों में हमें देने की मात्रा से अधिक देने की चेतना को समझना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे लिए कितना करता है, यह महत्वपूर्ण है; किंतु वह जो करता है, उसमें हमारी उपस्थिति को कितना महसूस करता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हमें भी केवल जिम्मेदारियाँ निभाने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों को यह बताना चाहिए कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य वस्तुओं से नहीं, स्मृतियों से बनता है। उपहार स्मृति का एक माध्यम है, प्रेम उसका आधार। जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन का भार उठाया है, उसके त्याग को पहचानना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है; और जो व्यक्ति हमारे जीवन में कभी-कभार आकर हमें याद करता है, उसके स्नेह को महत्व देना हमारी मानवीय संवेदना। दोनों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना उचित नहीं।

संबंधों की परिपक्वता वहीं से आरंभ होती है जहाँ हम यह समझने लगते हैं कि जो हमारे लिए सबसे अधिक करता है, उसे सबसे कम धन्यवाद मिला हो सकता है। और जो हमें सबसे छोटा उपहार देता है, उसके उपहार में शायद केवल वस्तु नहीं, हमारी स्मृति का प्रमाण छिपा होता है। इसलिए कभी उस व्यक्ति को भी उपहार दीजिए जो हमेशा आपके लिए करता आया है। कभी उसे बिना किसी अवसर के फूल दीजिए, कभी उसका हाथ पकड़कर कहिए कि "तुम्हारे होने से मेरा जीवन आसान हुआ है।" क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिसे हम सबसे अधिक अपना मानते हैं, उसे हम कई बार यह बताना भूल जाते हैं कि वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और शायद संबंधों का सबसे सुंदर दर्शन यही है—मनुष्य को केवल उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए नहीं, उसके अस्तित्व के लिए भी याद किया जाए। उपहार वस्तु से स्मृति बनता है, स्मृति से आत्मीयता और आत्मीयता से संबंध। पर जिस दिन हम उन अदृश्य उपहारों को पहचानना सीख लेते हैं, जो लोग अपने समय, श्रम, त्याग और मौन प्रेम के रूप में हमें देते रहे हैं, उसी दिन हमारे भीतर कृतज्ञता का वह दीप जलता है जिसकी रोशनी में संबंधों का वास्तविक सौंदर्य दिखाई देने लगता है।

लेखिका शिक्षाविद और मनोविज्ञानी है।



सोशल मीडिया बैटेल में लीड ले रही भाजपा

नौ साल की एंटी इंकम्बेंसी का नहीं दिख रहा असर

अभिनव सिन्हा

2027 यूपी चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने हिसाब से तैयारियां शुरु कर दी हैं। सभी दल सांगठनिक रूप से खुद को मजबूत करने में जुटे हैं, कुछ-कुछ दिन में सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा की ओर से किसी न किसी स्तर पर पदाधिकारियों की सूची जारी की जा रही है। मगर, इन सबसे इतर एक अन्य रणक्षेत्र यानी सोशल मीडिया पर अभी से पक्ष-विपक्ष दोनों ओर से हमले शुरु हो चुके हैं।

धारदार रही रणनीति

नौ साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा का चुनाव में सबसे तेज और कारगर हथियार सोशल मीडिया ही है। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी हर स्तर पर अपने संगठन को पूरा करने में जुटी है। प्रदेश स्तर पर बदलाव के साथ स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब रणनीति और धारदार होगी। चूंकि पार्टी लगातार दो बार से सत्ता में है, इसलिए एंटी इंकम्बेंसी भी महसूस हो रही है। ऐसे में जमीन पर लगातार कोई न कोई राजनीतिक अभियान चलाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही सोशल पर भी कैंपेन शुरु हो गए हैं।

बूथ स्तर तक बनाया संगठन

प्रदेश संयोजक घोषित हो के साथ अब सभी छह क्षेत्रों व 98 सांगठनिक जिलों के मंडल व बूथ स्तर तक टीमें बनाई जा रही हैं। सांगठनिक रूप से पार्टी में छह क्षेत्र काशी, अवध, ब्रज, कानपुर-बुंदेलखण्ड, गोरखपुर व पश्चिम हैं, इसके साथ ही 98 जिले व महानगर यूनिट भी हैं, जिनमें मंडल और उनके नीचे बूथ बनाये जाते हैं। सोशल मीडिया विभाग में इन सभी स्तरों पर एक संयोजक के साथ दो-तीन सह संयोजक व सदस्यों की टोली बनाई जा रही है, जो लगभग अंतिम रूप में हैं। बताया जा रहा है कि किसी दिन प्रदेश के सह संयोजकों की टीम घोषित हो जाएगी और उसके बाद नीचे की टीमें भी जारी हो जाएंगी।

तीसरी बार भी सपा ही टारगेट

तीसरी बार सत्ता के लिए संघर्ष में जुटी भाजपा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। सोशल मीडिया पर अभी से भाजपा ने अपने अभियान को धार देना शुरु कर दिया है। पार्टी के आधिकारिक फेसबुक पेज, एक्स व इंस्टाग्राम हैंडल के साथ यूट्यूब चैनल पर अपनी केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ सपा सरकार के दौर की आपराधिक घटनाओं के साथ घपले-घोटालों पर आधारित वीडियो व ग्राफिक्स लगातार फ्लोट हो रहे हैं।

सपा-कांग्रेस की बयानबाजी बनी मुसीबत

सपा पिछले दो विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद अब तीसरी बार मुख्य विपक्षी के तौर पर मैदान में है। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर भाजपा से अधिक सीटें जीत ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन बनता नहीं दिख रहा है। आये दिन दोनों दलों के नेताओं की ओर से चल रही तीखी बयानबाजी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। ऐसे में भाजपा का इको सिस्टम इसको लेकर बेहद आक्रामक रहता है और उनकी इस खींचतान को अपने हिसाब से उपयोग करता रहता है।

संख्या बल में भाजपा दिख रही भारी

पार्टियों के आधिकारिक हैंडल्स को अगर देखें तो भाजपा बाकी दोनों सपा और कांग्रेस से काफी आगे दिखाई पडती है। भाजपा के फेसबुक पर जहां छह मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, वहीं सपा के 4.8 मिलियन और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मात्र 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एक्स और इंस्टाग्राम पर भी लगभग यही हालत है। इसके अतिरिक्त भाजपा के विचार परिवार से प्रभावित कई फेसबुक पेज और एक्स हैंडल्स भी सक्रिय हैं, जो उसकी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए सपा पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में भले ही कुछ लोग भाजपा के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार भाजपा लीड लेती दिख रही है।

नैरेटिव बनाने में सपा नाकाम

सोशल मीडिया एक्सपर्ट बताते हैं कि अभी जमीन पर चुनाव प्रचार के जोर पकड़ने में कम से दो से तीन महीने हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार भाजपा खुद को मजबूत कर रही है। वहीं, सपा की ओर से आधिकारिक पेजों या हैंडल्स से कोई कैंपेन चलता नहीं दिख रहा है और न ही उनकी विचारधारा से प्रभावित लोग सोशल मीडिया पर कोई नैरेटिव बना पा रहे हैं।

बसपा लगभग गायब

प्रदेश के चौथे प्रमुख राजनीतिक दल यानी बहुजन समाज पार्टी की सोशल मीडिया पर बहुत उपस्थिति नहीं दिखती है। हालांकि, बसपा प्रमुख कुछ बड़े राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात जरूर रखती हैं जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर लेती हैं। वैसे उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे उनके भतीजे आकाश आनंद के बयानों की छोटे-छोटे क्लिप भी समर्थकों के द्वारा जारी की जाती रहती हैं। लेकिन, इनके सबके बावजूद सोशल मीडिया पर कोई खास मौजूदगी नजर नहीं आती है।



सम्मानजनक विदाई या 2027 के लिए भाजपा का बड़ा सियासी समीकरण?

अंडमान के नए एलजी बने डॉ. दिनेश शर्मा

शंकर स्वरुप शर्मा

उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल (LG) नियुक्त किया गया है। इस बड़े फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में अलग-अलग विश्लेषण और कयास लगाए जा रहे हैं। इसे "यूपी से निर्वासन" या "ब्राह्मणों की बेइज्जती" के रूप में देखना पूरी तरह सही नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे भाजपा के गहरे रणनीतिक और सांगठनिक समीकरण राजनीतिक विश्लेषकों और अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, इस कदम के पीछे निम्नलिखित मुख्य कारण और राजनीतिक संदेश माने जा रहे हैं:

1. राज्यसभा कार्यकाल की समाप्ति और 'सम्मानजनक पुनर्वास'डॉ. दिनेश शर्मा का राज्यसभा का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त होने वाला था। पार्टी के नियम और वरिष्ठ नेताओं को प्रशासनिक भूमिकाओं में शामिल करने की रणनीति के तहत, उनका कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पहले उन्हें उपराज्यपाल जैसी एक बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है। इसे पार्टी में उनके तीन दशकों के समर्पण का इनाम और एक 'सम्मानजनक पुनर्वास' (Honorable Rehabilitation) माना जा रहा है।
2. यूपी विधानसभा चुनाव (2027) की जमावट और नई लीडरशिप को मौकाउत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व यूपी की राजनीति में लगातार नए और युवा चेहरों को आगे बढ़ा रहा है। डॉ. दिनेश शर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक पद पर भेजकर, पार्टी नेतृत्व यूपी में स्थानीय स्तर पर नए समीकरणों और नए ब्राह्मण चेहरों को उभरने का अवसर
3. 'ब्राह्मण विरोधी' छवि के नैरेटिव को काटनाविपक्ष अक्सर भाजपा पर ब्राह्मण नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाता है। डॉ. दिनेश शर्मा को केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख (LG) बनाकर भाजपा ने यह संदेश दिया है कि उनके वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं का कद कम नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें देश की मुख्यधारा की महत्वपूर्ण और सुरक्षित भूमिकाओं में भेजा जा रहा है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं को अन्य राज्यों में राज्यपाल या उपराज्यपाल बनाकर भेजा जाता रहा है।
4. प्रशासनिक अनुभव का उपयोगडॉ. दिनेश शर्मा लखनऊ के लगातार दो बार मेयर, यूपी के शिक्षा मंत्री और उपमुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं। अंडमान और निकोबार जैसे सामरिक (Strategic) रूप से बेहद महत्वपूर्ण द्वीप समूह के लिए केंद्र सरकार को एक ऐसे अनुभवी और शांत छवि वाले नेता की जरूरत थी, जो सीधे राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय के साथ तालमेल बिठाकर काम कर सके।

राजनीतिक हलकों में इसे "शक्तियों का विघटन" नहीं, बल्कि "भूमिका का बदलाव" कहा जा रहा है। डॉ. दिनेश शर्मा ने खुद इस नियुक्ति पर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए इसे एक संवैधानिक जिम्मेदारी ।और जनसेवा का नया संकल्प बताया है। भाजपा ने इस चाल के जरिए एक तीर से दो निशाने साधे हैं—वरिष्ठ नेता को बड़ा सम्मान भी दे दिया और यूपी की भावी राजनीति के लिए रास्ता भी साफ कर लिया।



खामोश चीख और उस आखिरी फैसले का मनोविज्ञान: क्या हम अपनों को वक्त से पहले खो रहे हैं?



■ डॉ इंदु सुभाष
सोशल एक्टिविस्ट एवं रिलेशनल शिप काउंसलर

दुनिया के लिए कोई भी दिन एक सामान्य तारीख हो सकता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के कमरे में जो भीतर ही भीतर घुट रहा है, वहाँ एक खामोश चीख गूँज रही होती है, सन्नाटा चीख रहा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार, आत्महत्या आज युवाओं के बीच मौत का एक प्रमुख और चिंताजनक कारण है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर हमें यह गहराई से समझने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति अचानक इस रास्ते पर नहीं चलता। इसके पीछे महीनों, कभी-कभी सालों का वह दर्द होता है जिसे वह चाहकर भी किसी से कह नहीं पाता। जब कोई युवा अपनी मानसिक पीड़ा को अपने तक ही सीमित रखता है, तो उसका मन एक ऐसा रणक्षेत्र बन जाता है जहाँ वह हर रोज़ खुद से ही जंग हार रहा होता है।

क्यों घुटता है मन?—शक, सन्नाटे और उपेक्षा का चक्रव्यूह

जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है, तो बाहर की दुनिया का हर रंग, हर हंसी एक ताने जैसी लगती है। उसके मन में ये सवाल घूमने लगते हैं— "क्यों लोग खुश हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या सब मुझे देखकर हंस रहे हैं?"

घर के भीतर स्थिति तब और भयानक हो जाती है जब एक स्त्री यह सोचती है कि— "आखिर मेरा पति मुझ पर क्यों नहीं विश्वास करता? वह मुझे समय क्यों नहीं देता?" और जब वह कमरे में पहुँचती है, तो अचानक से सन्नाटा छा जाता है। उस वक्त उसके मन में यह शक घर कर जाता है कि— "क्या ये सब मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं?" यह अनकहापन और अविश्वास रिश्तों को एक ऐसे नरक में बदल देता है जहाँ साँस लेना भी दूभर हो जाता है।

स्त्री की व्यथा: सपनों का टूटना और "मैं क्यों खट रही हूँ?" का विचार

मात्र 27-28 साल की उम्र—वह पड़ाव जब जिंदगी के पंख फैलने ही चाहिए थे, हाथ में करियर की कोई उम्मीद होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह गोद में एक मासूम बच्चा और कंधों पर एक अनचाहे समझौते

की पूरी गृहस्थी आ जाती है।

करियर और मातृत्व का टकराव: जब वह अपनी उन सहपाठियों को देखती है जिन्होंने शादी नहीं की और जो अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं, तो एक हूक उठती है— "मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई?" बच्चे को पालने की नैतिक जिम्मेदारी और अपनी पहचान के छिन जाने का अफसोस, इस दोहरी भूमिका में इंसान थक जाता है।

बौद्धिक और भावनात्मक बेमेल: पति की जीवनशैली और सोच जब बिल्कुल मेल न खाए, और ऊपर से उपेक्षा मिले, तो इंसान अपनों के बीच रहकर भी सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है।

"मैं क्यों खट रही हूँ?" का विचार: जब दिन-रात बिना थके काम करने के बाद भी बदले में सिर्फ उपेक्षा मिले, और मन में यह विचार घर कर जाए कि "जब किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं, तो मैं क्यों खुद को घिस रही हूँ?"—तो यही वह बिंदु होता है जहाँ जीवन का मोह टूटने लगता है।

पुरुष का संघर्ष: बेरोजगारी, प्रेम में धोखा और टूटता आत्मविश्वास

इसी प्रकार, 28-29 साल का एक लड़का जब कई मोर्चों पर एक साथ घिर जाता है, तो उसकी मानसिक स्थिति उस ज्वालामुखी जैसी हो जाती है जिसकी आग बाहर नहीं दिखती, लेकिन भीतर सब कुछ जलाकर राख कर रही होती है।

बेरोजगारी और पेपर लीक: युवावस्था के सबसे ऊर्जावान साल किताबों में बीतने के बाद जब परीक्षा का लीक होना सामने आता है, तो यह सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि उस युवक की सालों की मेहनत का कत्ल है।

प्रेम में धोखा और अकेलापन: जब करियर के इस संघर्ष के बीच उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, और उस मोर्चे पर भी यदि उसे धोखा मिल जाए, तो वह अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है।

"कमाओगे तभी ब्याह होगा" और वैवाहिक कलह: समाज लड़के की योग्यता उसकी कमाई से तय करता है। वहीं, यदि वह विवाहित है और घर में लगातार तनाव व संवादहीनता है, तो बाहर रोजगार की अनिश्चितता और घर के भीतर अविश्वास—वह दोनों तरफ से पिस जाता है।

भारत में आत्महत्या के आंकड़े: एक गंभीर चेतावनी

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और सार्वजनिक स्वास्थ्य रिपोर्ट्स के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि यह संकट कितना व्यापक है:

जेंडर के आधार पर: देश में आत्महत्या करने वालों में पुरुषों का प्रतिशत (लगभग 73% से 73.5%) महिलाओं (लगभग 26.5% से 27%) की तुलना में काफी अधिक है। बुजुर्गों (60 वर्ष से अधिक) के वर्ग में भी लगभग 74% से 75% मामले बुजुर्ग पुरुषों के ही होते हैं।

युवा और सक्रिय वर्ग: कुल मामलों का लगभग 65% हिस्सा 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों का है। इसमें 18 से 30 वर्ष के युवा वर्ग की हिस्सेदारी करीब 33% है, जो करियर, परीक्षाओं, प्रेम और शुरुआती पारिवारिक दबावों से जूझ रहा होता है।

बढ़ता बुजुर्ग संकट: युवाओं के साथ-साथ अकेलेपन, स्वास्थ्य समस्याओं और उपेक्षा के कारण बुजुर्गों में भी आत्महत्या का ग्राफ तेजी से चिंताजनक रूप ले रहा है।

अंतिम समय का थॉट प्रोसेस: जब सब कुछ सुनसान हो जाता है

जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का पक्का इरादा कर लेता है और समय, साधन व तौर-तरीकों की योजना बना चुका होता है, तो उसके भीतर एक अत्यंत जटिल मानसिक स्थिति चल रही होती है:

अत्यंत असहायता (Helplessness): उसे महसूस होता है कि अब इस ब्रह्मांड में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है।

'हिम्मत' का भ्रम: लोग कहते हैं कि आत्महत्या करना कायरता है, लेकिन उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से यह उसकी अपनी ही जीवन-प्रवृत्ति (Survival Instinct) के खिलाफ जाकर लिया गया सबसे बड़ा और 'कठिन' कदम लग रहा होता है।

योजनाबद्ध खामोशी: वह रोते हुए नहीं, बल्कि अक्सर एक गहरी, डरावनी शांति के साथ समय और साधनों की पूरी योजना बनाता है ताकि उसका प्रयास 'विफल' न हो। यह उस गहरी हताशा का प्रतीक है जो अब पूरी तरह व्यवस्थित हो चुकी है।

प्रशासनिक और पुलिसिया तंत्र की क्रूरता: एक अदृश्य हत्यारा

विवाह या पारिवारिक विवादों के मामलों में पुलिस का अति-संवेदनशील और दमनकारी रवैया कई बार जानलेवा साबित होता है। कोर्ट में अपराध सिद्ध हुए बिना, केवल एक पक्ष के आरोप पर पुलिस का सीधे लड़के के घर में घुसकर युवक को अपमानित करना, उसके साथ मारपीट करना और मीडिया या समाज में उसकी बदनामी कर देना—यह किसी सामाजिक प्रताड़ना से कम नहीं है।

इस तरह की पक्षपाती क्रूरता और बेइज्जती से आहत होकर कई बार पूरा परिवार और विशेषकर वह युवा इस हद तक टूट जाता है कि उसे अपनी जान देना ही एकमात्र रास्ता नजर आने लगता है। उसके मन में यह विचार आने लगता है कि— "ना मैं रहूंगा, न कोई कोर्ट केस चलेगा, और न ही मेरे माता-पिता या बहन को इस अपमान और पुलिस के आतंक से गुजरना पड़ेगा।" पुलिस द्वारा अपने अधिकारों का इस तरह का दुरुपयोग और बिना जांच के किसी को अपराधी घोषित कर देना कानून के नाम पर एक निर्दोष की हत्या के समान है। इस व्यवस्थागत आतंक पर रोक लगना बेहद जरूरी है।

इस अंधकार से बाहर निकलने के व्यावहारिक और सामाजिक उपाय

जीवन जब चारों तरफ से घिर जाता है और घुटन दम तोड़ने लगती है, तो इस अंधी सुरंग से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ बुनियादी और ठोस बदलाव करने होंगे:

बचपन से 'शेयरिंग' और अटूट विश्वास की नींव: इसकी शुरुआत घर के बच्चों से होनी चाहिए। उन्हें अपनी भावनाएं और डर खुलकर 'शेयर' करना सिखाएं। साथ ही, खुद पर अटूट विश्वास (आस्था) जगाना सिखाएं कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, वह उनसे लड़ने की ताकत रखता है।

वोकेशनल ट्रेनिंग और आत्मनिर्भरता: युवाओं को केवल किताबी डिग्रियों के भरोसे छोड़ने के बजाय वोकेशनल ट्रेनिंग (व्यापार परक शिक्षा) को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वे युवा होते ही हुनरमंद बनकर अपना काम शुरू कर सकें। विशेषकर विवाह के बाद बहुएं या बेटियां भी घर से ऑनलाइन वर्क, बुटीक या खान-पान (फूड बिजनेस) जैसे काम शुरू कर सकती हैं।

बुजुर्गों की भूमिका और पारिवारिक सम्मान: माता-पिता और बुजुर्ग पीढ़ी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे युवाओं, विशेषकर अपनी पुत्रवधुओं को पूरा सपोर्ट दें और उनका सम्मान करें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अस्तित्व का सम्मान, करुणा का भाव और क्षमा करने की प्रवृत्ति बहुत जरूरी है। रिश्तों के बीच थोड़ा 'स्पेस' (निजी जगह) देना और बात-बात पर संवाद बनाए रखना गृहस्थी की गाड़ी को पटरी पर रखता है।

सामुदायिक मंच और मोहल्ले के छोटे 'क्लब्स': अपनी बात को बिना किसी डर के कहने के लिए मोहल्लों में साप्ताहिक या पाक्षिक छोटे-छोटे ग्रुप्स या क्लब्स बनाए जा सकते हैं, जहाँ लोग खुलकर अपनी मानसिक उलझनों और सुख-दुख को साझा कर सकें।

सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं (काउंसलिंग): हर समस्या का समाधान थाने या कोर्ट में नहीं होता। सरकार और समाज को मिलकर स्कूलों, डिग्री कॉलेजों और सामुदायिक स्तर पर आसानी से पहुँच योग्य (Easy to approach) काउंसलर्स की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग बिना किसी संकोच के अपनी मन की बात कह सकें।

जीवन जीने के लिए मिला है, घुटने के लिए नहीं। जब रिश्ते बोझ बन जाएं, तो उन्हें संवाद और समझ से सुधारें या जरूरत पड़ने पर खुद को उस घुटन से बाहर निकालें। आपकी सांसें किसी की जिद, पुलिस के खौफ या समाज के डर से बहुत अधिक कीमती हैं।



हिंदी : हमारी आवाज, हमारी स्मृति और हमारा आत्मसम्मान

शम्भू शरण सत्यार्थी

भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती। वह मनुष्य की स्मृतियों, संवेदनाओं, अनुभवों और सपनों को अपने भीतर सँजोकर रखती है। हम जिस भाषा में पहली बार माँ को पुकारते हैं, जिस भाषा में बचपन की कहानियाँ सुनते हैं, जिस भाषा में दुख में किसी का कंधा खोजते हैं और खुशी में किसी को आवाज देते हैं, वह भाषा हमारे जीवन का हिस्सा भर नहीं रहती, वह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। हिंदी भी हमारे लिए ऐसी ही भाषा है। वह करोड़ों लोगों की बोलचाल, संवेदना, साहित्य, पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन की भाषा है। इसलिए हिंदी दिवस केवल एक भाषा के सम्मान का अवसर नहीं बल्कि यह सोचने का दिन भी है कि हम अपनी भाषा के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हिंदी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उसका बोलने वाला कितने लोग हैं। असली सवाल यह है कि ज्ञान, शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, न्याय, विज्ञान और तकनीक की दुनिया में हिंदी को कितना सम्मान और अवसर मिला है।

हमारे समाज में अंग्रेजी का ज्ञान अक्सर योग्यता और प्रतिष्ठा का पर्याय मान लिया जाता है। अंग्रेजी जानना बुरा नहीं है। दूसरी भाषाएँ सीखना हमेशा मनुष्य की क्षमता को बढ़ाता है। समस्या तब पैदा होती है जब भाषा को बुद्धिमत्ता का प्रमाणपत्र बना दिया जाता है। किसी व्यक्ति की प्रतिभा, संवेदना, वैज्ञानिक दृष्टि या रचनात्मकता का मूल्य केवल इस आधार पर तय नहीं किया जा सकता कि वह अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, बुद्धिमत्ता का पैमाना नहीं।

दुर्भाग्य यह है कि आज भी अनेक परिवारों में बच्चे से हिंदी बोलने पर कोई विशेष गर्व नहीं किया जाता लेकिन अंग्रेजी के कुछ वाक्य बोल लेने पर उसे आधुनिक और योग्य समझ लिया जाता है। विद्यालयों में भी कई बार भाषा ज्ञान का माध्यम बनने के बजाय सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को होता है जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम की सुविधा नहीं। भाषा उनके सामने अवसर का दरवाजा खोलने के बजाय दीवार बन जाती है।

हिंदी की शक्ति केवल उसके मानक रूप में



नहीं, बल्कि उन तमाम लोकभाषाओं और बोलियों में भी है जिनसे उसका संसार समृद्ध हुआ है। भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, राजस्थानी और अनेक अन्य भाषिक रूप हिंदी क्षेत्र की सांस्कृतिक जमीन को सींचते हैं। इनके लोकगीतों, कहावतों, कथाओं और जीवन-अनुभवों ने हिंदी को व्यापक संवेदना दी है। इसलिए हिंदी को मजबूत करने का अर्थ इन भाषाओं को कमजोर करना नहीं हो सकता। हिंदी तभी समृद्ध होगी जब वह भारतीय भाषाओं के बीच पुल बनेगी, दीवार नहीं।

हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती ज्ञान की भाषा को लेकर है। यदि विज्ञान की पुस्तकें, चिकित्सा संबंधी जानकारी, कानून की भाषा, तकनीकी शिक्षा, शोध सामग्री और आधुनिक ज्ञान का बड़ा हिस्सा किसी व्यक्ति की पहुँच से केवल भाषा के कारण दूर हो जाए, तो यह केवल भाषाई समस्या नहीं रहती, यह सामाजिक न्याय का प्रश्न बन जाती है। ज्ञान पर किसी एक भाषा का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। भारत जैसे बहुभाषी देश में ज्ञान जितनी अधिक भारतीय भाषाओं में पहुँचेगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा।

हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने की बात भी इसी संदर्भ में समझनी होगी। यह जरूरी नहीं कि हर नौकरी में हिंदी ही पर्याप्त हो। जहाँ अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की वास्तविक आवश्यकता है, वहाँ उसका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जहाँ किसी काम को हिंदी में बेहतर ढंग से किया जा सकता है, वहाँ केवल अंग्रेजी के आकर्षण के कारण हिंदी को पीछे रखना उचित नहीं। भाषा को योग्यता का अनावश्यक अवरोध बनाने के बजाय हमें बहुभाषिक दक्षता को अपनी ताकत बनाना चाहिए।

न्याय और प्रशासन में भाषा का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। जिस नागरिक को अपने अधिकारों, सरकारी योजनाओं, नियमों और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी ही समझ में न आए, उसके लिए व्यवस्था कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, वह दूर ही रहेगी। लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ यह भी है कि शासन की भाषा नागरिक की समझ में आए। सरल, स्पष्ट और नागरिक-केंद्रित हिंदी इस दूरी को कम कर सकती है।

आज हिंदी के सामने एक नया संसार भी खुला है—डिजिटल संसार। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सामाजिक माध्यम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने भाषा के उपयोग की सीमाएँ बदल दी हैं। हिंदी अब केवल किताबों और अखबारों तक सीमित नहीं है। वह वीडियो, ध्वनि, डिजिटल शिक्षा, सामाजिक माध्यम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुँच रही है। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती है। हिंदी में मनोरंजन की सामग्री तो तेजी से बढ़ रही है, पर उच्च गुणवत्ता वाली ज्ञान सामग्री, वैज्ञानिक सामग्री, विश्वसनीय स्वास्थ्य जानकारी, तकनीकी प्रशिक्षण और शोधपरक सामग्री की अभी भी बड़ी आवश्यकता है। हमें ऐसी हिंदी चाहिए जो मनोरंजन करे, लेकिन केवल मनोरंजन तक सीमित न रहे; जो ज्ञान दे, प्रश्न पैदा करे और नई पीढ़ी को दुनिया समझने की क्षमता दे।

लेखकों, पत्रकारों और शिक्षकों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। हिंदी को कठिन शब्दों से सजाकर महान बनाने की जरूरत नहीं। भाषा की असली ताकत उसकी स्पष्टता और प्रभाव में होती है। सरल हिंदी का अर्थ कमजोर हिंदी नहीं है। गंभीर विचारों को सरल भाषा में व्यक्त करना अपने आप में एक बड़ी रचनात्मक क्षमता है। हमें ऐसी हिंदी चाहिए जो गाँव के पाठक को भी अपनी लगे और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को भी विचार दे सके।

हिंदी दिवस पर हम हर वर्ष भाषण देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं और कुछ दिनों तक हिंदी की चर्चा होती है। फिर जीवन अपनी सामान्य गति में लौट जाता है। शायद अब हमें इस परंपरा को बदलने की जरूरत है। हिंदी दिवस को केवल समारोह का दिन नहीं, बल्कि एक वर्ष के संकल्प का प्रारंभ बनाना चाहिए।

संकल्प भी ऐसे हों जिन्हें मापा जा सके। हम प्रतिदिन कम-से-कम 15 मिनट हिंदी पढ़ने का संकल्प लें और हर महीने एक अच्छी हिंदी पुस्तक, कहानी-संग्रह, निबंध या पत्रिका पढ़ें। एक वर्ष में कम-से-कम 12 पुस्तकों का लक्ष्य रखा जा सकता है। परिवार में सप्ताह में कम-से-कम तीन दिन बच्चों के साथ हिंदी में सहज संवाद किया जाए। विद्यालयों में प्रत्येक महीने कम-से-कम एक पठन, लेखन, वाद-विवाद या वक्तृत्व गतिविधि आयोजित हो और विद्यार्थियों को वर्ष में कम-से-कम छह अच्छी हिंदी पुस्तकों से परिचित कराया जाए। विज्ञान और तकनीक को हिंदी से जोड़ने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी वर्ष में कम-से-कम दो वैज्ञानिक या तकनीकी विषयों पर हिंदी में प्रस्तुति दे।

कार्यालय और संस्थान भी अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कर सकते हैं। जहाँ हिंदी में काम करना संभव है, वहाँ सप्ताह में कम-से-कम एक दिन हिंदी में कामकाज का अभ्यास किया जाए। प्रत्येक विभाग वर्ष में कम-से-कम पाँच उपयोगी मूल सामग्री—जैसे मार्गदर्शिका, सूचना-पुस्तिका, प्रशिक्षण सामग्री या डिजिटल संसाधन—हिंदी में तैयार करे। नागरिकों से जुड़ी आवश्यक सूचनाएँ सरल हिंदी में उपलब्ध कराई जाएँ। हिंदी का प्रयोग केवल अंग्रेजी सामग्री के अनुवाद तक सीमित न रहे; हिंदी में मूल ज्ञान-सामग्री तैयार करने पर भी जोर दिया जाए।

डिजिटल दुनिया में भी हम अपने हिस्से का लक्ष्य तय कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति महीने में कम-से-कम दो उपयोगी हिंदी सामग्री तैयार या साझा करे। शिक्षक, लेखक, पत्रकार और विशेषज्ञ कठिन विषयों को सरल हिंदी में समझाने की पहल करें। संस्थाएँ वर्ष में कम-से-कम एक विश्वसनीय हिंदी ज्ञान-संसाधन तैयार करें, चाहे वह विज्ञान, कानून, तकनीक, नागरिक अधिकार, शिक्षा या किसी अन्य उपयोगी विषय पर हो। यदि लाखों लोग छोटे-छोटे ऐसे संकल्पों को निभाएँ, तो हिंदी की दुनिया में बड़ा परिवर्तन संभव है।

लेकिन हिंदी के प्रति प्रेम का अर्थ दूसरी भाषाओं से घृणा करना नहीं है। हमें अंग्रेजी सीखनी है, दूसरी भारतीय भाषाएँ सीखनी हैं और दुनिया की भाषाओं से संवाद करना है। जितनी अधिक भाषाएँ हम सीखेंगे, हमारा संसार उतना ही विस्तृत होगा। हिंदी को मजबूत करने का उद्देश्य किसी भाषा को हटाना नहीं, बल्कि हिंदी को भी बराबरी का अवसर दिलाना है। भाषाएँ एक-दूसरे की दुश्मन नहीं होतीं; वे मनुष्य की विविध स्मृतियों और अनुभवों की अलग-अलग खिड़कियाँ होती हैं।

हिंदी को बचाने की नहीं, उसे बराबरी का अवसर देने की जरूरत है। उसे नारे नहीं, प्रयोग चाहिए; केवल उत्सव नहीं, निरंतर अभ्यास चाहिए। 14 सितंबर को इसलिए केवल हिंदी दिवस न मनाएँ, बल्कि इसे अपनी भाषा के प्रति अपने व्यवहार को बदलने का दिन बनाएँ।

एक वर्ष बाद जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमारे पास केवल हिंदी दिवस की तस्वीरें, भाषण और शुभकामना संदेश न हों। हमारे पास पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या हो, लिखी गई रचनाएँ हों, विद्यालयों की गतिविधियों का लेखा हो, तैयार की गई ज्ञान-सामग्री हो और हिंदी में किए गए वास्तविक काम का हिसाब हो। तभी हमारा हिंदी दिवस सचमुच सार्थक होगा।

हिंदी हमारी स्मृति है, हमारी अभिव्यक्ति है और हमारे भविष्य की संभावनाओं की भाषा भी है। जरूरत केवल इतनी है कि हम हिंदी के पक्ष में बोलने से आगे बढ़ें और हिंदी में काम करना शुरू करें।

योगी का 'मिशन यूपी'

युवा व महिलाओं से सीधा संवाद किया चुनावी जीत का शंखनाद

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनावी तैयारियों को लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर देना शुरू कर दिया है। पार्टी की रणनीति में युवा और महिलाएं महत्वपूर्ण केंद्र में दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं के बीच पार्टी की पहले से मजबूत पकड़ को बरकरार रखने के साथ-साथ अब युवा मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना भी बीजेपी की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सरकार की योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, रोजगार की तलाश कर रहे लोगों तथा ग्रामीण परिवारों तक पहुंच बनाने पर जोर दे रहे हैं। पिछले कुछ समय में सरकार की ओर से की गई कई घोषणाओं और शुरू किए गए अभियानों में इन वर्गों को विशेष महत्व दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में युवा मतदाताओं की संख्या राजनीतिक दलों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है। शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे मुद्दे युवाओं के बीच खास महत्व रखते हैं। इसी वजह से सरकार की योजनाओं में रोजगार और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों को प्रमुखता मिलती दिखाई दे रही है।

बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में फरवरी-मार्च 2027 में संभावित विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के बड़े नेता संगठनात्मक तैयारियों में जुटे हैं। पार्टी की कोशिश बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय रखने और स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क बढ़ाने की है।

चुनावी राजनीति में बूथ स्तर का संगठन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी स्तर पर मतदाताओं से सीधा संपर्क, स्थानीय समस्याओं की जानकारी और सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम होता है। ऐसे में बीजेपी संगठन की मजबूती के साथ-साथ सरकार की योजनाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए समाज के अलग-अलग वर्गों से संवाद बढ़ा रहे हैं। महिलाओं और युवाओं के अलावा ग्रामीण परिवारों, विद्यार्थियों और रोजगार से जुड़े लोगों के लिए भी कई योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए महिलाओं तक पहुंच

महिलाओं के बड़े समूह तक पहुंच बनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार और ग्रामीण परिवारों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य की 2.91 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छह जिलों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह घोषणा की गई। इसके अगले दिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर 2026 से लागू होगा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संपर्क ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं तथा परिवारों से रहता है। बच्चों के पोषण, प्रारंभिक देखभाल और महिला एवं बाल विकास से जुड़े कार्यों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सरकार की ओर से उनके मानदेय में वृद्धि को केवल आर्थिक निर्णय के रूप में ही नहीं, बल्कि महिला कार्यबल को प्रोत्साहित करने वाले कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' अभियान की शुरुआत भी की। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अभियान के जरिए आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका, बच्चों के पोषण और महिलाओं से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

महिलाओं की सुरक्षा और भागीदारी पर जोर

महिलाओं को सुरक्षा बलों में अधिक भागीदारी देने की दिशा में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाए हैं।



प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) में महिलाओं के लिए तीन बटालियनें बनाई गई हैं। इन बटालियनों के नाम उदा देवी, झलकारी बाई और अवंतीबाई के नाम पर रखे गए हैं। इनमें एक बटालियन लखनऊ, दूसरी गोरखपुर और तीसरी बदायूं में स्थित है। सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था में उनकी भूमिका को मजबूत करना भी है।

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ सामाजिक भागीदारी का मुद्दा भी लगातार राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन रहा है। ऐसे में सरकारी नौकरियों, सुरक्षा बलों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय स्तर के रोजगार कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आने वाले समय में महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है।

'जेन जी' को जोड़ने की कोशिश

युवा मतदाताओं को लेकर भी सरकार की गतिविधियां बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में घोषणा की कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत 50 हजार छात्राओं को स्कूटर देगी। इसके अलावा उन्होंने अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा भी की है।

युवाओं के बीच रोजगार और करियर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हैं। ऐसे में सरकारी भर्तियों, नियुक्ति पत्र, कौशल प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुख शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों पर सरकार का जोर युवाओं को सीधे प्रभावित करने वाला क्षेत्र है।

सरकार की कोशिश केवल पारंपरिक सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। कौशल विकास और निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

'प्रोजेक्ट प्रवीण' के जरिए कौशल विकास

यूपी सरकार छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट प्रवीण' चला रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस परियोजना के तहत यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन का लक्ष्य राज्य के 3000 से अधिक छात्रों को रोजगारोन्मुख क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 31 प्रशिक्षण संस्थानों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर 30 सितंबर तक प्रशिक्षण शुरू करना अनिवार्य किया गया है।

प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को परिधान निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं यानी IT-ITeS, प्रबंधन और अन्य रोजगारोन्मुख क्षेत्रों से संबंधित कौशल प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्री तक सीमित रखने के बजाय उन्हें रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है।

आज के समय में कंपनियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में युवाओं को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने वाला कदम माना जाता है।

युवाओं के जरिए परिवारों तक पहुंच

सरकार की रणनीति केवल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं तक सीमित नहीं है। पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाले युवाओं और नवविवाहित जोड़ों को भी सरकारी योजनाओं के दायरे में लाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना इसके प्रमुख उदाहरणों में शामिल है। सरकार के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में 17,758 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में 72,448 जोड़ों के सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया है। सामूहिक विवाह योजना का सीधा संबंध आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से है। शादी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अवसर पर सरकारी सहायता मिलने से परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने की कोशिश की जाती है। इस तरह की योजनाएं एक साथ कई परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाने का माध्यम बनती हैं।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो युवाओं और नवविवाहित परिवारों तक पहुंच का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि एक परिवार के भीतर कई मतदाता होते हैं। इसलिए किसी योजना का प्रभाव केवल लाभार्थी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार और सामाजिक संपर्कों तक भी पहुंच सकता है।

स्वयं सहायता समूहों से ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने की कोशिश

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का ग्रामीण आजीविका मिशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार के अनुसार इस मिशन से करीब 10.5 लाख स्वयं-सहायता समूह (SHG) जुड़े हुए हैं।

इन समूहों के माध्यम से करीब 1.25 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के आत्मनिर्भर बनने का दावा किया गया है। इनमें 28 लाख से ज्यादा 'लखपति दीदियां' भी शामिल हैं।

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को बचत, ऋण, छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ने का माध्यम बन रहे हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भूमिका मजबूत होने के साथ-साथ परिवार की आय में भी योगदान बढ़ता है।

ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 65,544 ग्राम संगठन और 3,298 क्लस्टर-लेवल फेडरेशन भी काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में संगठनों की मौजूदगी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामूहिक रूप से जोड़ने का एक व्यापक नेटवर्क तैयार करती है।

योजनाओं के साथ चुनावी रणनीति

उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं और युवाओं का महत्व आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए और बढ़ गया है। बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर बूथों को मजबूत करने की तैयारी कर रही है, वहीं सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभार्थी वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है।

महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी, सुरक्षा बलों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े कार्यक्रम हैं तो युवाओं के लिए नियुक्ति, कौशल प्रशिक्षण, छात्राओं के लिए स्कूटर और रोजगारोन्मुख योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव कितना व्यापक होगा और इसका राजनीतिक असर किस रूप में सामने आएगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। हालांकि इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में युवा और महिला मतदाता राजनीतिक दलों की रणनीति के केंद्र में रहने वाले हैं।

2027 की राह में बड़ा सवाल

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों का विस्तार कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार युवा मतदाताओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। नई पीढ़ी रोजगार, शिक्षा, डिजिटल अवसर, कौशल विकास और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर की जा रही घोषणाएं इसी बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच देखी जा रही हैं। अब सवाल यह है कि इन योजनाओं का जमीनी असर कितना दिखाई देता है और युवा तथा महिला मतदाता इसे किस नजरिए से देखते हैं।

2027 के विधानसभा चुनाव तक अभी समय है। ऐसे में आने वाले महीनों में सरकार की नई घोषणाएं, रोजगार के अवसर, महिला कल्याण योजनाएं और संगठन की बूथ स्तर की सक्रियता उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।





अयोध्या से वाराणसी तक बदली तस्वीर

यूपी की संस्कृति अब बन रही है डिजिटल कंटेंट की नई कहानी

उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान अब केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रह गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और अन्य सांस्कृतिक केंद्रों की कहानियां सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्री, वेब कंटेंट और डिजिटल फिल्मों का हिस्सा बन रही हैं।

योगी सरकार की पर्यटन नीति में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नए तरीके से प्रस्तुत करने पर लगातार जोर दिखाई देता है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटकों को आकर्षित करना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करना भी है।

आज दर्शक किसी जगह को केवल घूमने के लिए नहीं देखता। वह उसके इतिहास, खान-पान, संस्कृति, लोककला और स्थानीय कहानियों को भी जानना चाहता है। यही वजह है कि डिजिटल क्रिएटर्स के लिए उत्तर प्रदेश बेहद बड़ा कंटेंट हब बन सकता है।

अयोध्या की धार्मिक विरासत, वाराणसी की आध्यात्मिक संस्कृति और ब्रज क्षेत्र की कृष्ण परंपरा अलग-अलग तरह की कहानियां प्रस्तुत करती हैं। इन क्षेत्रों की लोककलाएं, संगीत और पारंपरिक खान-पान भी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं।

सरकार की ओर से पर्यटन स्थलों के विकास के साथ-साथ उनकी ब्रांडिंग और प्रचार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों से परिचित कराने की कोशिश भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

डिजिटल कंटेंट के विस्तार का फायदा स्थानीय कलाकारों को भी मिल सकता है। लोक संगीतकार, शिल्पकार, फोटोग्राफर, गाइड और छोटे व्यवसाय डिजिटल माध्यम से अपने काम को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचा सकते हैं।

यह बदलाव उत्तर प्रदेश की संस्कृति को एक नए रूप में सामने ला रहा है। जहां पहले किसी शहर की पहचान केवल उसके प्रसिद्ध स्थल से होती थी, अब पूरी स्थानीय संस्कृति ही एक कहानी बन सकती है।

सरकार के लिए यह पर्यटन को रोजगार से जोड़ने का अवसर है और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लगातार नए विषय खोजने का।

आने वाले समय में यूपी की सांस्कृतिक विरासत फिल्मों और टीवी तक सीमित न रहकर शॉर्ट वीडियो, वेब सीरीज, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया स्टोरीटेलिंग का भी बड़ा हिस्सा बन सकती है।



योगी सरकार का नया विकास मॉडल एक्सप्रेसवे अब सिर्फ सड़क नहीं, बनेंगे औद्योगिक गलियारों की रीढ़

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे अब सिर्फ तेज सफर का माध्यम नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालिया समीक्षा के दौरान अधिकारियों को एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की सोच साफ है कि सड़क बने और उसके आसपास उद्योग न आएं, तो विकास का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। इसी वजह से एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को एक-दूसरे से जोड़ने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों को नई कनेक्टिविटी दी है। अब सरकार इस कनेक्टिविटी को रोजगार और निवेश से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यह है कि जिन क्षेत्रों से होकर एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं, वहां केवल यातायात नहीं बल्कि वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी वातावरण तैयार किया जाए। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा उन इलाकों को मिल सकता है जो पारंपरिक रूप से बड़े औद्योगिक केंद्रों से दूर रहे हैं। अगर एक्सप्रेसवे के आसपास उद्योग विकसित होते हैं तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। किसानों और स्थानीय कारोबारियों के लिए भी नई आर्थिक गतिविधियां पैदा हो सकती हैं।

सरकार की प्राथमिकता परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी है। जमीन की उपलब्धता, बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी और परिवहन जैसी जरूरतों को औद्योगिक विकास की योजना से जोड़ना इसी रणनीति का हिस्सा है। यह मॉडल उत्तर प्रदेश की उस व्यापक नीति से जुड़ता है जिसमें बुनियादी ढांचे को आर्थिक विकास का आधार बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के किनारे यदि उद्योग, लॉजिस्टिक्स हब और व्यवसायिक गतिविधियां विकसित होती हैं, तो प्रदेश के लिए नई आर्थिक पट्टियां तैयार हो सकती हैं।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका प्रभाव केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी नई औद्योगिक गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है।

यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क केवल यात्रा को आसान बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उद्योग, रोजगार और कारोबार को गति देने वाला आर्थिक नेटवर्क बन सकता है। यही वजह है कि योगी सरकार का एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक विकास मॉडल अगस्त की सबसे चर्चित विकास खबरों में शामिल है।

डिजिटल प्रभाव

अवसर, चुनौतियाँ और सामाजिक ज़िम्मेदारी



■ मोहित मौर्य
लेखक एवं स्वतंत्र स्तंभकार

21वीं सदी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंसानी ज़िंदगी को आकार देने वाली सबसे ताकतवर इकाई में से एक बन गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, ब्लॉग, पॉडकास्ट और डिजिटल कम्युनिटी लोगों के सोचने, बातचीत करने, सीखने और फ़ैसले लेने के तरीके पर असर डालते हैं। जहाँ डिजिटल असर ने शिक्षा, इनोवेशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए अनगिनत मौके बनाए हैं, वहीं इसने लोगों, संगठनों और सरकारों की इन प्लेटफॉर्म का सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़िम्मेदारी भी बढ़ा दी है। इसलिए, डिजिटल असर और सामाजिक ज़िम्मेदारी आपस में जुड़े हुए हैं और एक भरोसेमंद और सबको साथ लेकर चलने वाले डिजिटल समाज को बनाने के लिए ज़रूरी हैं।

डिजिटल असर का मतलब है लोगों, संगठनों या ऑनलाइन कम्युनिटी की डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए राय, व्यवहार और फ़ैसलों को आकार देने की क्षमता। असर डालने वाले, शिक्षक, पत्रकार, सेलिब्रिटी, बिज़नेस और आम यूज़र कंटेंट बनाकर और शेयर करके इस असर में योगदान देते हैं। एक पोस्ट, वीडियो या ट्वीट कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुँच सकता है। जानकारी के इस तेज़ी से फैलने ने कम्युनिकेशन को बदल दिया है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म जागरूकता, वकालत और सामाजिक बदलाव के लिए ताकतवर टूल बन गए हैं।

डिजिटल असर का सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों को शिक्षित और मज़बूत बनाने की इसकी क्षमता है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एजुकेशनल रिसोर्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन और करियर गाइडेंस तक पहुँच देते हैं। स्टूडेंट्स वर्चुअल क्लास में जा सकते हैं, प्रोफेशनल्स ऑनलाइन लर्निंग के ज़रिए अपनी स्किल्स सुधार सकते हैं, और नागरिक नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में जानकारी रख सकते हैं। डिजिटल कैंपेन ने एनवायरनमेंटल कंज़र्वेशन, महिला एम्पावरमेंट, सोशल वेलफेयर , मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और डिज़ास्टर रिलीफ की कोशिशों को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है। छोटे एंटरप्रेन्योर और लोकल कारीगर अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ऑडियंस को दिखा सकते हैं, जिससे उनके व्यापार का दायरा बढ़ जाता है। सरकारें और पब्लिक इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज़ को कम्युनिकेट करने, पब्लिक सर्विसेज़ देने और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर हैं। इस तरह, डिजिटल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए एक कैटलिस्ट बन गया है।

हालांकि, डिजिटल इन्फ्लुएंस की बढ़ती ताकत गंभीर चुनौतियाँ भी पेश करती है। गलत जानकारी और फेक न्यूज़ के तेज़ी से फैलने से कन्फ्यूज़न, पैनिक और सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। हेल्थ, पॉलिटिक्स या पब्लिक सेफ्टी के बारे में गलत जानकारी के नुकसानदायक नतीजे हो सकते हैं। साइबरबुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट, हेट स्पीच और डिजिटल फ्रॉड बड़ी चिंता बन गए हैं, खासकर बच्चों और यंग एडल्ट्स के लिए। पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल, आइडेंटिटी थेफ्ट और प्राइवेसी वायलेशन ने ज़िम्मेदार डिजिटल बिहेवियर की ज़रूरत को और बढ़ा दिया है।

एक और चुनौती AI एल्गोरिदम का बढ़ता असर है जिससे सिर्फ इंटरेस्ट वाले कंटेंट ही सुझाव में आते हैं और दायरा सीमित हो जाता है। इससे इको चैंबर बन सकते हैं जहाँ यूज़र्स को सिर्फ़ अपनी जैसी राय ही सुनने को मिलती है, जिससे कंस्ट्रक्टिव बातचीत कम होती है और सोशल पोलराइजेशन बढ़ता है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस एंग्जायटी, स्ट्रेस, लो सेल्फ-एस्टीम और डिजिटल एडिक्शन पैदा करके मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल सकती है।

इस मामले में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी हो जाती है। डिजिटल ज़माने में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है टेक्नोलॉजी का इस तरह से इस्तेमाल करना जिससे समाज को फ़ायदा हो और नुकसान कम से कम हो। हर डिजिटल सिटिज़न की ज़िम्मेदारी है कि वह जानकारी शेयर करने से पहले उसे वेरिफाई करे, दूसरों की राय का सम्मान करे, नफ़रत या गलत जानकारी फैलाने से बचे, और ऑनलाइन बातचीत में सम्मान बनाए रखे। डिजिटल इन्फ्लुएंसर की ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा होती है क्योंकि उनका कंटेंट बड़ी ऑडियंस तक पहुँचता है। इन्फ्लुएंसर नुकसानदायक ट्रेंड या गलत लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के बजाय शिक्षा, पर्यावरण की स्थिरता, स्वास्थ्य, जेंडर इक्वालिटी और कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में जागरूकता बढ़ाकर समाज में योगदान दे सकते हैं।

यूपी टी-20 लीग में गूंजा क्रिकेट का रोमांच, लखनऊ और काशी की भिड़ंत बनी सुर्खियों में

उत्तर प्रदेश में क्रिकेट का उत्साह इस अगस्त अपने चरम पर नजर आया। उत्तर प्रदेश टी-20 लीग के मुकाबलों ने राज्य में स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं को बड़ा मंच दिया है। लखनऊ और काशी की टीमों के बीच मुकाबले खास तौर पर चर्चा में रहे और क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे।

इस तरह की लीग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि लगातार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने का अनुभव भी चाहिए।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में अलग-अलग क्षेत्रों से प्रतिभाशाली खिलाड़ी सामने आते हैं। कई खिलाड़ियों को बड़े मंच पर खेलने का अवसर नहीं मिल पाता। राज्य स्तरीय टी-20 प्रतियोगिताएं ऐसे खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन सकती हैं।

लखनऊ के इकाना स्टेडियम जैसे आधुनिक क्रिकेट मैदानों में होने वाले मुकाबलों से प्रदेश में क्रिकेट संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। दर्शकों को स्थानीय टीमों से जुड़ने का मौका मिलता है और खिलाड़ियों के लिए घरेलू प्रशंसक तैयार होते हैं।

यूपी टी-20 लीग की खास बात यह भी है कि इसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाओं को खेलने का मौका मिलता है। अनुभवी खिलाड़ी युवाओं को मैदान पर दबाव संभालने और मैच की स्थिति को समझने में मदद कर सकते हैं।

लखनऊ फाल्कन्स और काशी रुद्रास के बीच हुए मुकाबलों ने इसी प्रतिस्पर्धा को दिखाया।

क्रिकेट के अलावा इस तरह के आयोजन से खेल से जुड़े दूसरे क्षेत्रों को भी फायदा होता है। स्थानीय स्टेडियम, मीडिया, खेल पत्रकारिता, फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ती हैं।

योगी सरकार की खेल नीति में खिलाड़ी पहचान, प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, शिक्षा और रोजगार जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

इसका मतलब यह है कि खेल को केवल प्रतियोगिता के रूप में नहीं बल्कि करियर और अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

यूपी टी-20 लीग इसी बदलती खेल संस्कृति की तस्वीर पेश करती है। आने वाले समय में प्रदेश से और अधिक क्रिकेट प्रतिभाएं राष्ट्रीय मंच तक पहुंचें, इसके लिए ऐसे टूर्नामेंट अहम भूमिका निभा सकते हैं।





जापान की नजर यूपी पर क्यों?
योगी सरकार का निवेश मॉडल बना ग्लोबल चर्चा का विषय

उत्तर प्रदेश और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अगस्त में महत्वपूर्ण गतिविधियां देखने को मिलीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए राज्य को मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए संभावनाशील स्थान के रूप में प्रस्तुत किया।

जापानी कंपनियों की पहचान उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण, तकनीकी दक्षता और अनुशासित उत्पादन प्रणाली के लिए है। उत्तर प्रदेश के लिए जापानी निवेश का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे स्थानीय उद्योगों को वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिल सकता है।

योगी सरकार का जोर केवल फैक्ट्री लगाने पर नहीं बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट, स्किल सेंटर और तकनीकी सहयोग पर भी है। यही पहल राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

यदि विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करती हैं तो उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत होगी। इससे स्किल डेवलपमेंट संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ सकता है।

जापान के साथ साझेदारी में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग भी महत्वपूर्ण विषय है। वैश्विक उद्योग अब उत्पादन के साथ पर्यावरणीय स्थिरता पर भी ध्यान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश यदि हरित उद्योगों और स्वच्छ तकनीक को आकर्षित करता है तो यह राज्य की औद्योगिक छवि को और मजबूत कर सकता है।

सरकार ने जापानी प्रतिनिधियों के साथ पर्यटन और उद्योग दोनों क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी बातचीत की है।

इससे एक व्यापक तस्वीर सामने आती है। उत्तर प्रदेश खुद को केवल घरेलू बाजार वाला राज्य नहीं बल्कि वैश्विक निवेश और उत्पादन नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है।

जापान के साथ सहयोग इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ तकनीक, कौशल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ती है तो इसका असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ सकता है।

अगस्त की गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक निवेशकों से केवल निवेश मांगने के बजाय उन्हें दीर्घकालिक साझेदारी का प्रस्ताव देने की कोशिश कर रहा है।

खेलों में यूपी की नई उड़ान
मैदान से करियर तक खिलाड़ियों के लिए बदल रहा माहौल



उत्तर प्रदेश में खेल अब केवल शौक नहीं बल्कि करियर के विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहा है। सरकार की खेल नीति में खिलाड़ी पहचान, प्रशिक्षण, शिक्षा, रोजगार और खेल विज्ञान को महत्व दिया गया है।

इस बदलाव की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी को शुरुआती स्तर से ही सही प्रशिक्षण मिले। केवल प्रतियोगिता आयोजित करने से खेल संस्कृति मजबूत नहीं होती। खिलाड़ियों को प्रशिक्षक, आधुनिक सुविधाएं, फिटनेस, पोषण और मानसिक तैयारी भी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में खेल सुविधाओं का विस्तार इसी दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। क्रिकेट के अलावा हॉकी, एथलेटिक्स, कुश्ती, शूटिंग, बैडमिंटन और अन्य खेलों में भी स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलने की जरूरत है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। समस्या अक्सर संसाधनों और अवसरों की होती है। यदि जिला और क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर खेल ढांचा तैयार होता है तो छोटे शहरों के खिलाड़ी भी आगे आ सकते हैं।

खेल को शिक्षा से जोड़ना भी जरूरी है। कई युवा खिलाड़ी इस डर से खेल छोड़ देते हैं कि खेल में करियर का भविष्य निश्चित नहीं है। अगर प्रशिक्षण के साथ शिक्षा और रोजगार का रास्ता स्पष्ट हो तो परिवार भी बच्चों को खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

योगी सरकार की खेल नीति में खिलाड़ी कल्याण और रोजगार जैसे पहलुओं को शामिल करना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

खेलों का विकास प्रदेश की युवा आबादी के लिए भी महत्वपूर्ण है। खेल फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना को बढ़ावा देता है। साथ ही इससे खिलाड़ियों के अलावा कोच, फिजियो, फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स मैनेजर और अन्य पेशेवरों के लिए रोजगार पैदा होते हैं।

उत्तर प्रदेश में खेलों का भविष्य अब केवल बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गांवों और छोटे जिलों से निकलने वाली प्रतिभाओं को भी समान अवसर मिलना जरूरी है।

यदि प्रशिक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और करियर सपोर्ट एक साथ आगे बढ़ते हैं तो यूपी आने वाले समय में देश के प्रमुख स्पोर्ट्स टैलेंट हब के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सकता है।

यूपी की तस्वीर

निवेश, संस्कृति और टेक्नोलॉजी का नया कॉम्बिनेशन



उत्तर प्रदेश की वैश्विक छवि पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदलने की कोशिशों के दौर से गुजर रही है। अब राज्य को केवल बड़ी आबादी वाले प्रदेश के रूप में नहीं बल्कि निवेश, उद्योग, पर्यटन, टेक्नोलॉजी और संस्कृति के संयुक्त केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

जापान के साथ बढ़ता संपर्क इसका उदाहरण है। राज्य सरकार विदेशी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिसर्च, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट में भागीदारी के लिए आमंत्रित कर रही है।

दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए प्रस्तुत कर रहा है। जापानी प्रतिनिधिमंडल का प्रदेश के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों से परिचित होना इसी दिशा में महत्वपूर्ण गतिविधि रही।

इस रणनीति का उद्देश्य राज्य की अलग-अलग ताकतों को एक साथ जोड़ना है। उद्योग को जमीन और बाजार चाहिए, पर्यटन को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं चाहिए तथा टेक कंपनियों को कुशल मानव संसाधन की जरूरत होती है।

उत्तर प्रदेश के पास इन क्षेत्रों में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। चुनौती यह है कि इन्हें एक संगठित इकोसिस्टम में बदला जाए।

योगी सरकार का मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योग से, उद्योग को रोजगार से और पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है।

इसका असर छोटे शहरों तक भी पहुंच सकता है। अगर निवेश केवल बड़े महानगरों तक सीमित न रहे और अलग-अलग क्षेत्रों में औद्योगिक तथा पर्यटन गतिविधियां विकसित हों तो क्षेत्रीय विकास का संतुलन बेहतर हो सकता है।

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान भी इस वैश्विक ब्रांडिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और आगरा जैसे स्थान दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण रखते हैं। यानी यूपी की नई कहानी केवल उद्योग की नहीं है। इसमें संस्कृति, पर्यटन, तकनीक, निवेश और युवा शक्ति सभी शामिल हैं।

यही कारण है कि अगस्त में उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय निवेश और पर्यटन रणनीति लगातार चर्चा में रही।



यूपी में स्टार्टअप की नई कहानी

आइडिया से इंडस्ट्री तक पहुंचाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर अगस्त में नई हलचल दिखाई दी। नई स्टार्टअप नीति के तहत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, स्पेसटेक, डिफेंसटेक, एग्रीटेक और हेल्थटेक जैसे उभरते क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की दिशा स्पष्ट की है।

इसका महत्व इसलिए है क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन कारोबार तक सीमित नहीं हैं। डीप टेक और रिसर्च आधारित कंपनियां आने वाले समय की बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती हैं।

उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की रणनीति में इनक्यूबेशन, प्रोटोटाइप, सीड फंडिंग, मेंटरिंग और उद्योग से संपर्क जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चुनौती आइडिया से प्रोडक्ट तक पहुंचना होती है। बहुत से युवा शानदार विचार लेकर आते हैं लेकिन उन्हें बाजार, तकनीकी मार्गदर्शन और शुरुआती निवेश की जरूरत होती है। इनक्यूबेटर इस समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। यहां युवा उद्यमियों को ऑफिस स्पेस, तकनीकी सहायता, मेंटर और निवेशकों से संपर्क जैसे अवसर मिल सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की नई नीति में जिला स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा देने की सोच भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप संस्कृति केवल नोएडा और लखनऊ तक सीमित न रहकर छोटे शहरों और जिलों तक पहुंच सकती है। ODOP जैसे स्थानीय उत्पादों के साथ स्टार्टअप को जोड़ने से पारंपरिक कारोबार को भी डिजिटल बाजार मिल सकता है। इससे स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बेहतर हो सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि वितरित की, जिससे सरकार की इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका दिखाई देती है। अगर यह इकोसिस्टम मजबूत होता है तो यूपी के युवा नौकरी तलाशने वाले ही नहीं बल्कि नौकरी देने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं। यही बदलाव उत्तर प्रदेश की नई बिजनेस कहानी को सबसे दिलचस्प बनाता है।

जापान से लेकर ग्लोबल कंपनियों तक यूपी में निवेश का नया माहौल क्यों बन रहा है?

उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर अगस्त का महीना काफी सक्रिय रहा। राज्य सरकार ने जापानी कंपनियों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक के साथ संपर्क बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि यूपी को केवल बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि उत्पादन, तकनीक और निर्यात का केंद्र बनाया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों से उत्तर प्रदेश को अपना "सेकेंड इंडस्ट्रियल होम" बनाने की अपील की। बातचीत में मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिसर्च, तकनीक, स्किल सेंटर और ग्लोबल सप्लाई चेन को भी महत्व दिया गया।

यह रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक निवेशक केवल जमीन या बाजार नहीं देखते। वे कनेक्टिविटी, बिजली, लॉजिस्टिक्स, कुशल श्रम, नीति स्थिरता और प्रशासनिक सुविधा जैसे पहलुओं को भी देखते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य में इन क्षेत्रों को मजबूत करने पर लगातार काम हो रहा है। एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों की योजना इसी व्यापक रणनीति से जुड़ी है।

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फायदा यह हो सकता है कि एक जगह केवल एक फैक्ट्री न लगे बल्कि उसके आसपास सप्लायर, लॉजिस्टिक्स कंपनियां, वेयरहाउस और सेवा क्षेत्र भी विकसित हों।

इससे स्थानीय व्यापार को भी फायदा मिल सकता है। बड़े उद्योगों के आसपास छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए नई सप्लाई चेन तैयार हो सकती है।

उत्तर प्रदेश का बड़ा घरेलू बाजार भी निवेशकों के लिए आकर्षण का कारण है। लेकिन सरकार अब बाजार के साथ उत्पादन और निर्यात की क्षमता को भी सामने रख रही है।

जापान के साथ सहयोग में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर भी महत्वपूर्ण है। वैश्विक कंपनियां अब पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को प्राथमिकता दे रही हैं।

यदि उत्तर प्रदेश निवेश, तकनीक और कौशल को एक साथ आगे बढ़ाने में सफल होता है तो राज्य का बिजनेस इकोसिस्टम और मजबूत हो सकता है।

अगस्त की निवेश गतिविधियां इसी बदलती कारोबारी तस्वीर की ओर संकेत करती हैं।



पूर्वांचल में उद्योग की नई दस्तक

गोरखपुर और आसपास बदल रही कारोबारी तस्वीर

पूर्वांचल लंबे समय तक औद्योगिक विकास के मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पीछे माना जाता रहा। लेकिन हालिया वर्षों में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने पर सरकार का विशेष ध्यान दिखाई दे रहा है।

Invest UP की हालिया गतिविधियों में गोरखपुर औद्योगिक क्षेत्र को लेकर नई योजनाओं और निवेश संभावनाओं का उल्लेख हुआ है।

पूर्वांचल के लिए औद्योगिक विकास का महत्व केवल उद्योग लगाने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध स्थानीय रोजगार, कारोबार और पलायन से भी जुड़ा है।

अगर युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिलते हैं तो उन्हें बड़े शहरों की ओर जाने की मजबूरी कम हो सकती है।

गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति भी इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना सकती है। बेहतर सड़क संपर्क और औद्योगिक आधार के साथ यह क्षेत्र आसपास के जिलों के कारोबार को भी गति दे सकता है।

सरकार की रणनीति में औद्योगिक क्षेत्रों के साथ लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को जोड़ना महत्वपूर्ण है। केवल उद्योग लगाने से विकास नहीं होता। उसके लिए कच्चे माल की आवाजाही, तैयार माल की आपूर्ति, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी जरूरी हैं।

पूर्वांचल में खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी संभावनाएं हैं। कृषि उत्पादों को स्थानीय स्तर पर प्रोसेस करने से किसानों और उद्योग दोनों को फायदा हो सकता है।

यूपी सरकार की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी पहलों में भी इसी तरह की वैल्यू चेन विकसित करने पर जोर दिखाई देता है।

अगर पूर्वांचल में उद्योग, कृषि और लॉजिस्टिक्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। गोरखपुर की बदलती कारोबारी तस्वीर इस बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।



आस्था से विकास तक: योगी के उत्तर प्रदेश में तीर्थ और परम्परा का नया अध्याय

उत्तर प्रदेश को समझना हो तो उसके तीर्थों, मंदिरों, घाटों और धार्मिक परम्पराओं को समझना जरूरी है। यह वह प्रदेश है जहां अयोध्या की रामभक्ति, काशी की आध्यात्मिकता, मथुरा-वृंदावन की कृष्ण परम्परा, प्रयागराज का संगम, चित्रकूट की रामायण परम्परा और विंध्याचल की शक्ति आराधना एक साथ दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इन्हीं धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान वाले स्थलों को विकास, सुविधाओं और पर्यटन से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है।

कांवड़ यात्रा से तीर्थ विकास तक

सावन आते ही उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कांवड़ियों की यात्रा एक बड़े धार्मिक आयोजन का रूप ले लेती है। दूर-दराज से श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परम्परा नहीं, बल्कि जनभागीदारी और सामाजिक आस्था का भी बड़ा उदाहरण है।

ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा सहायता, पेयजल और श्रद्धालुओं की सुविधा जैसी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। योगी सरकार के दौर में कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बदलाव केवल व्यवस्था तक सीमित नहीं है। धार्मिक यात्राओं को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने का अर्थ है कि श्रद्धालुओं को अपनी आस्था की यात्रा में कम से कम असुविधा हो और स्थानीय स्तर पर भी आयोजन का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे। कांवड़ यात्रा इस व्यापक दृष्टिकोण का एक उदाहरण है, जिसमें धार्मिक परम्परा और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था एक साथ दिखाई देती है।

अयोध्या: आस्था के केंद्र का बदलता स्वरूप

उत्तर प्रदेश की धार्मिक यात्रा में अयोध्या का स्थान सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। श्रीराम की नगरी अयोध्या लंबे समय से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रही है। राम मंदिर के निर्माण के बाद शहर के धार्मिक और पर्यटन महत्व को नई पहचान मिली है। अयोध्या में मंदिर परिसर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों का विकास, धार्मिक मार्गों की सुविधाएं, घाटों का विकास, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं शहर को एक आधुनिक तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा सकते हैं।

अयोध्या का विकास इस बात का उदाहरण भी है कि किसी धार्मिक शहर की पहचान केवल उसके मंदिरों से नहीं बनती। उसके घाट, गलियां, बाजार, स्थानीय कला, खान-पान, संस्कृति और लोगों की जीवनशैली भी उस धार्मिक अनुभव का हिस्सा होती है। इसलिए अयोध्या का नया स्वरूप केवल निर्माण का विषय नहीं, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान गढ़ने का प्रयास है जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर की

परम्परागत आत्मा भी बनी रहे।

काशी: परम्परा के साथ आधुनिक सुविधाएं

काशी को भारत की आध्यात्मिक चेतना के सबसे पुराने केंद्रों में गिना जाता है। बाबा विश्वनाथ का धाम और गंगा के घाट देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रखते हैं। काशी विश्वनाथ धाम के विकास ने मंदिर और गंगा घाट के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही को अधिक सुविधाजनक बनाया है। इसके साथ शहर के धार्मिक और पर्यटन ढांचे में भी बदलाव देखने को मिला है।

काशी की विशेषता यह है कि यहां आधुनिकता और परम्परा एक-दूसरे के सामने खड़ी दिखाई नहीं देतीं, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है। पुराने मंदिर, गलियां और घाट आज भी शहर की पहचान हैं, वहीं नई सुविधाएं श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने का माध्यम बन रही हैं। यह मॉडल उत्तर प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है—ऐसा विकास जिसमें विरासत को मिटाकर नया निर्माण करने के बजाय विरासत को संरक्षित रखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

मथुरा-वृंदावन और ब्रज की सांस्कृतिक पहचान

भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और उनकी लीलाभूमि वृंदावन उत्तर प्रदेश की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहां मंदिरों के अलावा होली, जन्माष्टमी, झूलन और अन्य ब्रज परम्पराएं धार्मिक संस्कृति को जीवंत बनाती हैं। ब्रज क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों, धार्मिक स्थलों, मार्गों और श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रज की विशेषता यह है कि यहां धार्मिक पर्यटन केवल मंदिर दर्शन तक सीमित नहीं है। यह संगीत, लोककला, नृत्य, खान-पान, हस्तशिल्प और स्थानीय परम्पराओं से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में तीर्थ विकास का सीधा लाभ स्थानीय कलाकारों, दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों तक पहुंच सकता है।

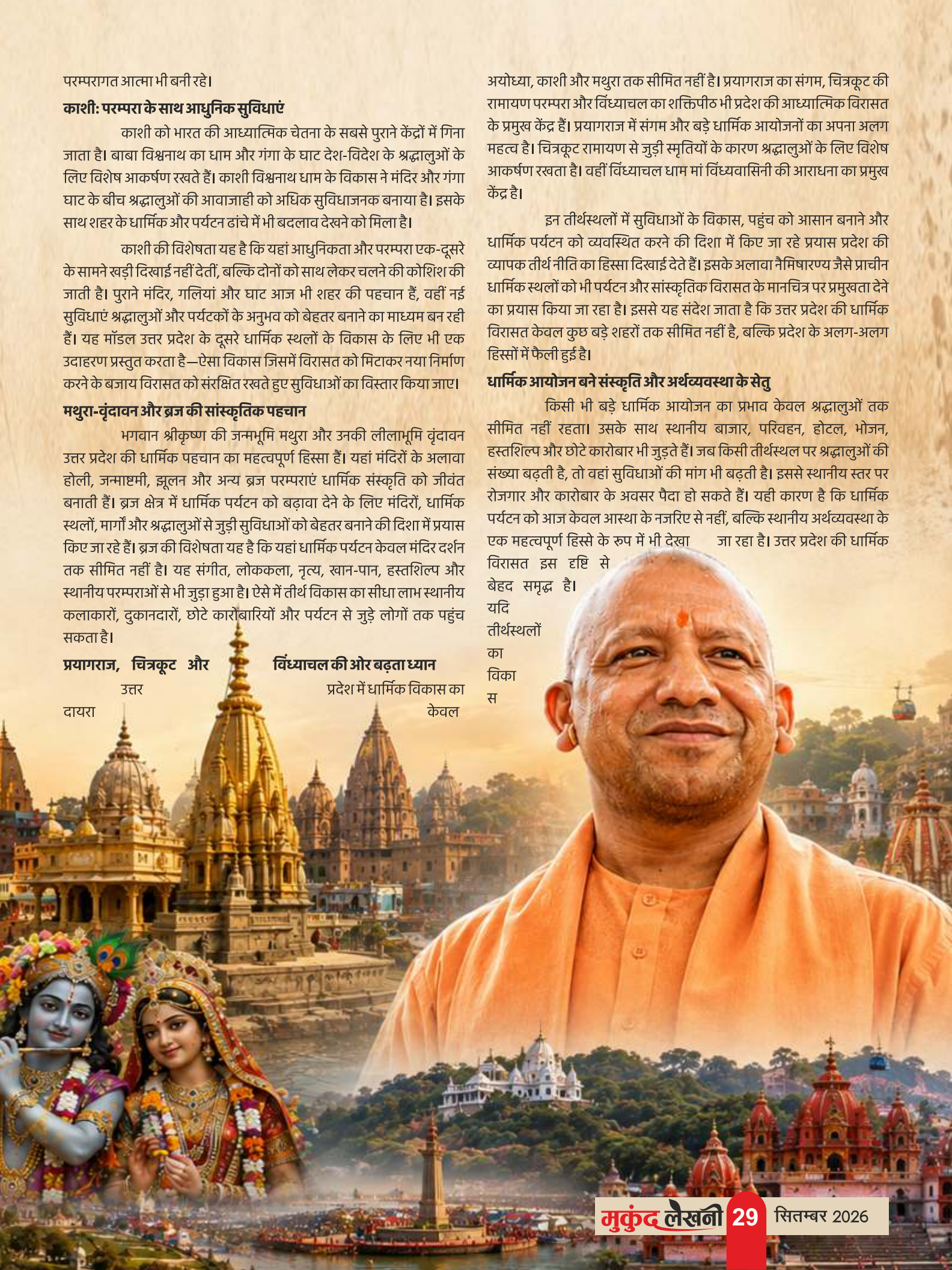
प्रयागराज, चित्रकूट और विंध्याचल की ओर बढ़ता ध्यान

उत्तर प्रदेश में धार्मिक विकास का दायरा केवल अयोध्या, काशी और मथुरा तक सीमित नहीं है। प्रयागराज का संगम, चित्रकूट की रामायण परम्परा और विंध्याचल का शक्तिपीठ भी प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत के प्रमुख केंद्र हैं। प्रयागराज में संगम और बड़े धार्मिक आयोजनों का अपना अलग महत्व है। चित्रकूट रामायण से जुड़ी स्मृतियों के कारण श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रखता है। वहीं विंध्याचल धाम मां विंध्यवासिनी की आराधना का प्रमुख केंद्र है।

इन तीर्थस्थलों में सुविधाओं के विकास, पहुंच को आसान बनाने और धार्मिक पर्यटन को व्यवस्थित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रदेश की व्यापक तीर्थ नीति का हिस्सा दिखाई देते हैं। इसके अलावा नैमिषारण्य जैसे प्राचीन धार्मिक स्थलों को भी पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के मानचित्र पर प्रमुखता देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे यह संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक विरासत केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में फैली हुई है।

धार्मिक आयोजन बने संस्कृति और अर्थव्यवस्था के सेतु

किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन का प्रभाव केवल श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रहता। उसके साथ स्थानीय बाजार, परिवहन, होटल, भोजन, हस्तशिल्प और छोटे कारोबार भी जुड़ते हैं। जब किसी तीर्थस्थल पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, तो वहां सुविधाओं की मांग भी बढ़ती है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार के अवसर पैदा हो सकते हैं। यही कारण है कि धार्मिक पर्यटन को आज केवल आस्था के नजरिए से नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक विरासत इस दृष्टि से बेहद समृद्ध है। यदि तीर्थस्थलों का विकास



योजनाबद्ध तरीके से होता है, तो धार्मिक पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार को मजबूती देने वाला माध्यम बन सकता है।

विरासत और आधुनिकता के बीच संतुलन जरूरी

धार्मिक स्थलों का विकास जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उनकी मूल पहचान को बचाए रखना। किसी तीर्थ की खूबसूरती केवल चमकदार इमारतों में नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके इतिहास, परम्परा, स्थानीय संस्कृति और लोगों के जीवन में होती है। इसलिए तीर्थ विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा पर भी समान ध्यान देना आवश्यक है।

योगी सरकार की धार्मिक पहलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करते हुए तीर्थस्थलों की प्राचीन आत्मा को सुरक्षित रखा जाए। यदि यह संतुलन कायम रहता है, तो उत्तर प्रदेश का धार्मिक विकास केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत बन सकता है।

एक नई धार्मिक पर्यटन पहचान

उत्तर प्रदेश की धार्मिक यात्रा आज एक नए मोड़ पर दिखाई देती है। कांवड़ यात्रा जैसे पारम्परिक आयोजनों की व्यवस्थाओं से लेकर अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज, चित्रकूट, विंध्याचल और नैमिषारण्य जैसे तीर्थस्थलों के विकास तक, धार्मिक आस्था को आधुनिक सुविधाओं और पर्यटन से जोड़ने की कोशिश व्यापक रुप ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धार्मिक पहलों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें आस्था और विकास को एक-दूसरे का विरोधी मानने के बजाय साथ लेकर चलने का प्रयास दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश केवल धार्मिक स्थलों का प्रदेश नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक विरासत को नए स्वरुप में प्रस्तुत करने वाला प्रदेश भी बन रहा है। आने वाले समय में इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि विकास की इस यात्रा में श्रद्धा, संस्कृति, विरासत, पर्यावरण और स्थानीय समाज—इन सभी के बीच कितना बेहतर संतुलन बनाया जाता है। क्योंकि तीर्थ केवल पहुंचने की जगह नहीं होता। तीर्थ एक अनुभव है, एक परम्परा है और पीढ़ियों से चली आ रही आस्था की वह कहानी है, जिसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे दुनिया के सामने नए रुप में प्रस्तुत करना।

यूपी की नई Startup Policy में AI से SpaceTech तक फोकस,

युवाओं के लिए खुल रहे टेक्नोलॉजी के दरवाजे

उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति में भविष्य की तकनीकों को विशेष महत्व दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, स्पेसटेक, डिफेंसटेक, एग्रीटेक और हेल्थटेक जैसे क्षेत्रों को स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ने की दिशा स्पष्ट की गई है।

यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय की अर्थव्यवस्था केवल पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर नहीं होगी। नई तकनीकें ही कारोबार और रोजगार के नए क्षेत्र तैयार करेंगी।

उत्तर प्रदेश में बड़ी युवा आबादी है और तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है। यदि उन्हें स्टार्टअप के लिए बेहतर वातावरण मिलता है तो राज्य से नई टेक कंपनियां निकल सकती हैं।

इनक्यूबेशन सेंटर इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवा उद्यमियों को आइडिया विकसित करने, प्रोटोटाइप तैयार करने और बाजार तक पहुंचने में विशेषज्ञों की सहायता मिल सकती है।

स्टार्टअप नीति में जिला स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा देने की सोच भी खास है। इससे छोटे शहरों के युवाओं को भी टेक उद्यमिता की ओर बढ़ने का अवसर मिल सकता है।

किसी छोटे शहर का युवा स्थानीय समस्या का तकनीकी समाधान विकसित कर सकता है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में ऐसे स्टार्टअप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की Startup Policy में ODOP की ताकत को भी नए उद्यमों से जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है।

इससे पारंपरिक उद्योग और आधुनिक तकनीक के बीच नया संबंध बन सकता है।

अगर यह मॉडल सफल होता है तो यूपी की टेक अर्थव्यवस्था केवल बड़ी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेगी। स्थानीय स्टार्टअप और युवा उद्यमी भी प्रदेश की आर्थिक पहचान का हिस्सा बनेंगे।



Google के साथ यूपी की नई टेक पार्टनरशिप
खेती से गांव तक पहुंचेगी डिजिटल क्रांति



उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में Google के साथ हुई साझेदारी खास चर्चा में रही। सरकार की यूपी एग्रीज पहल के तहत Google और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में तकनीक और डेटा आधारित समाधान को बढ़ावा देना है।

आज खेती केवल मौसम पर निर्भर रहने वाला काम नहीं रह गया है। किसान को बाजार, मौसम, फसल की स्थिति, जल प्रबंधन और उत्पादन से जुड़ी कई जानकारियों की जरूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट आधारित तकनीक कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। Google DeepMind द्वारा विकसित कृषि संबंधी AI मॉडल खेतों की स्थिति और कृषि गतिविधियों को समझने के लिए उपग्रह आधारित जानकारी का इस्तेमाल करते हैं।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े कृषि राज्य में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर किसान को समय रहते मौसम या फसल से जुड़ी जानकारी मिलती है तो वह बेहतर निर्णय ले सकता है। सरकार और टेक कंपनियों के बीच सहयोग से यह तकनीक स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकसित की जा सकती है।

इस पहल का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल समावेशन है। तकनीक का लाभ केवल बड़े किसानों या शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सरल डिजिटल सेवाएं पहुंचाना जरूरी है। अगर मोबाइल आधारित सेवाओं, डिजिटल सलाह और स्थानीय भाषा में जानकारी का विस्तार होता है तो किसान तकनीक को आसानी से अपना सकते हैं।

यूपी एग्रीज का उद्देश्य कृषि को भविष्य की अर्थव्यवस्था से जोड़ना इसी व्यापक बदलाव का संकेत देता है। यह साझेदारी उत्तर प्रदेश को कृषि और टेक्नोलॉजी के संगम का नया मॉडल बनाने का अवसर देती है। आने वाले समय में खेत में काम करने वाला किसान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाला विशेषज्ञ एक ही कृषि इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं।

मेडिकल और टेक करियर पर योगी सरकार का फोकस, युवाओं के लिए बदल रही प्रोफेशनल दुनिया

उत्तर प्रदेश में प्रोफेशनल करियर के अवसरों को लेकर अगस्त में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां सामने आईं। मेडिकल क्षेत्र में इंटर्नशिप से जुड़े युवाओं के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया, जबकि टेक और स्टार्टअप क्षेत्र में नई नीतियों के जरिए युवाओं को उभरते क्षेत्रों की ओर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल शिक्षा में इंटर्नशिप केवल प्रशिक्षण का चरण नहीं होती। यह वह समय होता है जब छात्र वास्तविक अस्पताल व्यवस्था में काम करते हैं और डॉक्टर के पेशे की व्यावहारिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। सरकार द्वारा इंटर्न के लिए बेहतर सहायता उपलब्ध कराना मेडिकल शिक्षा के माहौल को मजबूत करने की दिशा में देखा जा सकता है।



दूसरी ओर टेक सेक्टर में करियर तेजी से बदल रहा है। AI, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, स्पेसटेक और हेल्थटेक जैसे क्षेत्र युवाओं के लिए नए करियर विकल्प तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की दिशा में स्पष्ट संकेत देती है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में युवा पारंपरिक करियर विकल्पों के साथ नई तकनीकी विशेषज्ञताओं पर भी ध्यान दे सकते हैं। विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाना जरूरी होगा। यूपी में यदि शिक्षा, स्किल और उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनता है तो युवाओं को पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम हो सकती है। करियर का भविष्य अब केवल डिग्री से तय नहीं होगा। वास्तविक कौशल, अनुभव और बदलती तकनीक को समझने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होगी।

यूपी सरकार की नई नीतियां इसी बदलती प्रोफेशनल दुनिया के लिए आधार तैयार करने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं।

सेमीकंडक्टर से लेकर AI तक: यूपी क्यों बनना चाहता है भारत का अगला टेक हब?

उत्तर प्रदेश अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में केवल आईटी सर्विस सेक्टर तक सीमित रहने की बजाय हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और डीप टेक की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। राज्य की सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य चिप निर्माण, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सेंसर, सिलिकॉन फोटोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है।

सेमीकंडक्टर आज लगभग हर आधुनिक तकनीक का आधार है। मोबाइल फोन, कार, मेडिकल उपकरण, रक्षा प्रणाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीनों तक में चिप की जरूरत होती है। इसलिए चिप निर्माण की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत के राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।



उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती और अवसर दोनों बड़े हैं। हाई-टेक उद्योग के लिए कुशल इंजीनियर, बेहतर बिजली व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स, अनुसंधान संस्थान और विश्वसनीय सप्लाई चेन जरूरी होती है। राज्य की नई स्टार्टअप नीति भी AI और डीप टेक क्षेत्रों पर जोर देती है।

यदि स्टार्टअप, विश्वविद्यालय और उद्योग एक साथ काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी का स्थानीय इकोसिस्टम मजबूत हो सकता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्र पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों का विस्तार आसपास के इलाकों में भी नए अवसर पैदा कर सकता है।

यूपी सरकार का जापानी कंपनियों से तकनीक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर सहयोग बढ़ाने का प्रयास भी इसी दिशा से जुड़ा हुआ है। अगर राज्य हाई-टेक उद्योग के लिए जरूरी इकोसिस्टम तैयार करता है तो यूपी देश के प्रमुख टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।

चर्चा

इलेक्ट्रिक बसों से बदलता यूपी का ट्रांसपोर्ट मॉडल, शहरों में बढ़ेगी ग्रीन मोबिलिटी

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार महत्वपूर्ण विषय बन गया है। राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन में निजी भागीदारी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है।

इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि शहरों में प्रदूषण और ईंधन आधारित परिवहन पर निर्भरता कम करने की दिशा में मदद मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में यातायात लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना जरूरी है। यदि लोगों को आरामदायक और विश्वसनीय बस सेवा मिलती है तो निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम हो सकती है।

इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। इसके लिए बस टर्मिनल और परिवहन नेटवर्क की योजना को तकनीकी जरूरतों के साथ जोड़ना होगा। सरकार द्वारा आधुनिक बस टर्मिनलों के विकास और इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क को आगे बढ़ाने की दिशा में निजी क्षेत्र को शामिल करने की योजना इसी व्यापक बदलाव का हिस्सा है।



इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से ऑटो सेक्टर में भी नए रोजगार और व्यवसाय के अवसर पैदा हो सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन, बैटरी सर्विस, इलेक्ट्रिक वाहन रखरखाव और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे नए क्षेत्र विकसित होंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सप्लाई चेन विकसित होने से ऑटो इंडस्ट्री को भी फायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश यदि सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सफल मॉडल तैयार करता है तो यह दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।

एक्सप्रेसवे और ऑटो इंडस्ट्री का नया कनेक्शन यूपी में बढ़ेगी लॉजिस्टिक्स की ताकत



उत्तर प्रदेश का विस्तृत एक्सप्रेसवे नेटवर्क ऑटो और लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए बड़ा अवसर पैदा कर सकता है। सरकार अब एक्सप्रेसवे को औद्योगिक गलियारों से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है।

ऑटो उद्योग के लिए सड़क संपर्क बेहद महत्वपूर्ण है। वाहन निर्माण के लिए अलग-अलग हिस्सों की सप्लाई और तैयार वाहनों की आवाजाही लगातार होती रहती है। यदि औद्योगिक क्षेत्र एक्सप्रेसवे के करीब विकसित होते हैं तो कंपनियों के लिए परिवहन आसान हो सकता है। इससे समय और लॉजिस्टिक्स लागत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इसे ऑटो और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। राज्य देश के कई बड़े बाजारों से जुड़ा है। एक्सप्रेसवे के किनारे वेयरहाउसिंग, सर्विस सेंटर और सप्लाई चेन गतिविधियों के विकसित होने की संभावना है।

सरकार का लक्ष्य केवल सड़क बनाना नहीं बल्कि सड़क के आसपास आर्थिक गतिविधियों का इकोसिस्टम तैयार करना है। यही वजह है कि औद्योगिक कॉरिडोर की अवधारणा को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है।

ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता महत्व भी इस बदलाव को नई दिशा दे सकता है। भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, बैटरी और चार्जिंग से जुड़े उद्योगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण होगी। यदि उत्तर प्रदेश अपने एक्सप्रेसवे नेटवर्क को ऑटो, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ने में सफल रहता है तो राज्य का औद्योगिक नक्शा और बदल सकता है।



यूपी के युवाओं के लिए रोजगार का नया रोडमैप

सरकारी नौकरी से आगे बढ़कर स्किल और स्टार्टअप पर जोर

उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए करियर के अवसर अब केवल सरकारी नौकरी तक सीमित रखने की बजाय स्किल, स्टार्टअप और निजी क्षेत्र के रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को गति देने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है।

सरकारी नौकरी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण विकल्प है, लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग, टेक कंपनियां, स्टार्टअप और स्वरोजगार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यूपी की नई स्टार्टअप नीति में युवाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इनक्यूबेशन और वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके साथ उद्योगों के साथ स्किल डेवलपमेंट को जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। जापानी कंपनियों के साथ बातचीत में भी स्किल सेंटर और इंडस्ट्री-रेडी वर्कफोर्स पर जोर दिया गया।

इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में नौकरी पाने के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं होगी। तकनीकी कौशल, संचार क्षमता और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण होगा। यूपी के युवाओं के लिए यह बदलाव अवसर भी है और चुनौती भी। जो युवा नई तकनीक, AI, डेटा, डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी स्किल सीखेंगे, उनके लिए नए क्षेत्रों में अवसर खुल सकते हैं। सरकार, विश्वविद्यालय और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल इस प्रक्रिया को मजबूत कर सकता है। यूपी यदि रोजगार को स्किल और निवेश से जोड़ने में सफल रहता है तो राज्य के युवा केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि नए व्यवसाय और रोजगार पैदा करने वाले भी बन सकते हैं।

खेत में AI और आसमान से डेटा

यूपी की खेती में साइंस का नया दौर शुरू



उत्तर प्रदेश में कृषि को विज्ञान और तकनीक से जोड़ने की कोशिश अब नई दिशा ले रही है। Google और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग के जरिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक और डेटा आधारित समाधान लागू करने की कोशिश की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल चैटबॉट या मोबाइल एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है। कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्र में भी AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।

Google DeepMind के कृषि संबंधी मॉडल खेतों की स्थिति को समझने और कृषि गतिविधियों की निगरानी में उपग्रह आधारित जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी तकनीक किसानों को यह समझने में मदद कर सकती है कि फसल की स्थिति कैसी है, जमीन पर क्या बदलाव हो रहा है और मौसम या अन्य परिस्थितियों का खेती पर क्या असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि प्रदेश की बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि से जुड़ी है।

वैज्ञानिक तकनीक के जरिए खेती को ज्यादा सटीक बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसान का पारंपरिक ज्ञान खत्म हो जाएगा। बल्कि वैज्ञानिक जानकारी और किसान के अनुभव को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपी एग्रीज का उद्देश्य कृषि को भविष्य की अर्थव्यवस्था से जोड़ना इसी बदलाव का हिस्सा है। भविष्य की खेती में किसान, वैज्ञानिक, टेक कंपनी और बाजार एक साथ काम कर सकते हैं। यदि मौसम और फसल की जानकारी समय पर मिलती है तो किसान बेहतर निर्णय ले सकता है। इसी तरह डिजिटल मार्केट जानकारी से वह अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार तलाश सकता है। साइंस का यह उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है।

उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती यह होगी कि इस तकनीक को सरल और सुलभ बनाया जाए, ताकि इसका लाभ केवल बड़े किसानों तक सीमित न रहे। अगर यह मॉडल सफल होता है तो यूपी कृषि और टेक्नोलॉजी के संगम का बड़ा उदाहरण बन सकता है।

2 GOOD CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES

— BUILDING TRUST, DELIVERING QUALITY —



One Roof All Solutions

पूजन से लेकर गृह प्रवेश तक – हर कदम पर आपका साथ

- Residential Construction (with Material)
- Commercial Construction (with Material)
- Map Design & Vastu Checking
- 2D Plan / 3D Elevation Structural Drawing Plumbing | Electrical Carpenter Drawings
- Interior Renovation (Flat / Home / Office / Commercial)
- Technical Site Supervision & Project Management

- Loan Estimate & Financial Guidance
- LDA Map Approval
- Plot & Flat Sale / Purchase
- Govt Civil Contractor
- Home Pre-Delivery Inspection
- Architects Collaboration
- Land Survey Proposal ₹50/sq ft (2 Bigha Survey + Printout, 2D Road Map, Future Extension)

Structure Starting at ₹1300/sq ft (with Material)

Navratri / Dussehra Special Offer

- Engineer + Architect Guidance
- Transparent Agreement
- CCTV | No Tension
- Labour + Material Purchasing Handled
- Quality Checks at Every Stage

Aapka Sapna Hamara Saath

Quality se compromise nahin

Our Work Area

LUCKNOW

(Head Office)

Now Serving **PAN UTTAR PRADESH**

Our Branches & Service Locations

- Lucknow
- Gonda
- Barabanki
- Kanpur
- Sultanpur
- Ayodhya
- Gorakhpur



+ All Districts of Uttar Pradesh

Construction Packages

Structure Starting ₹1300/sq ft (with Material)

Navratri / Dussehra Special Offer

Minimum Plot Requirement
(Commercial) : 2000 sq ft & G+2
(Residential) : G+1 (2000 sq ft)

Free with Every Contract

- Mapping + Elevation
- Supervision & Equipment Guidance
- Earthing
- 200 ft Borewell
- 3D Elevation
- Vastu Consultation
- Project Supervision Report
- Interior Layout Ideas

Environment Day Special
Complimentary Pot Garden Area


Residential


Commercial


2D/3D Design


Interior


Site Supervision


Planning



Contact Us Today

+91 84180 21802

2goodconstruction@gmail.com

Founder
Er. Ritik Pathak
(Civil Engineer)
13+ Experience

Anna University Chennai

Plan → Management → Supervision → Execution → Final Handover

Aaj hi apne sapno ke ghar ki planning ke liye humein contact karein!

#2GoodGroup #ConstructionManagement #BuildYourDreamHome #Lucknow #UttarPradesh #ResidentialConstruction #CommercialConstruction #Vastu #MapDesign

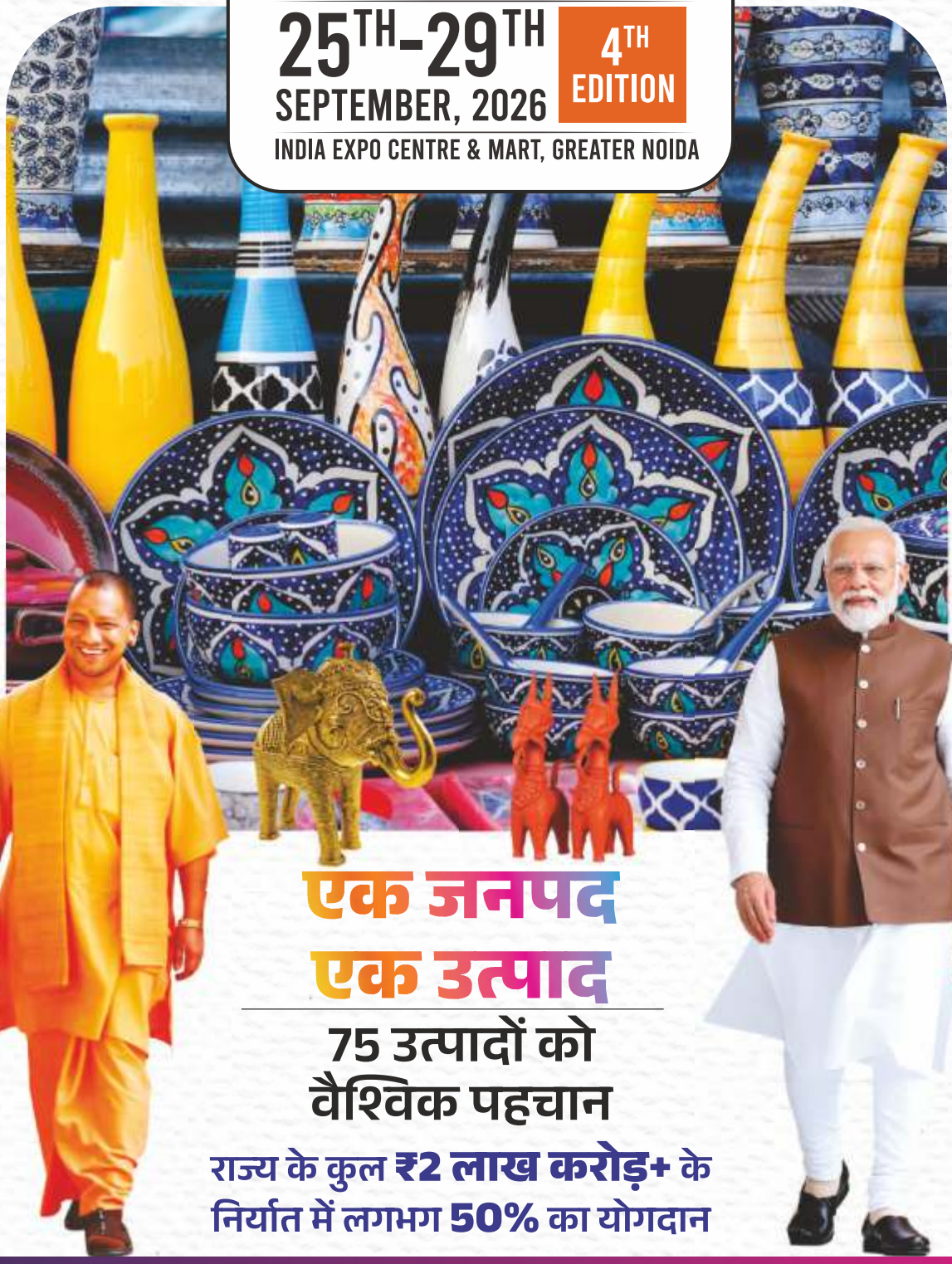
एक जनपद एक उत्पाद
उत्तर प्रदेश

UP INTERNATIONAL TRADE SHOW

25TH-29TH SEPTEMBER, 2026

4TH EDITION

INDIA EXPO CENTRE & MART, GREATER NOIDA



एक जनपद एक उत्पाद

75 उत्पादों को वैश्विक पहचान

राज्य के कुल **₹2 लाख करोड़+** के निर्यात में लगभग **50%** का योगदान

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP